साक्षात्कार
श्री मोहनराव भागवत............. 5
महंगाई विरोधी रैली
दिल्ली...................................... 9
उत्तर प्रदेश............................. 10
बिहार, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश... 11
हरियाणा.................................. 12
मध्य प्रदेश.............................. 13
लेख
और कितना रुलाएगी महंगाई
—जयंती लाल भण्डारी..... 15
सौ दिन की चांदनी, फिर अंधेरी..
—सिद्धार्थ भाटिया............ 17
देश पर मंडराती अकाल की छाया
—हरेन्द्र प्रताप................. 23
कोई दीर्घकालीन योजना नहीं
—टी. एस. आर सुब्रमण्यम.... 25
खेती पर रेती
—सत्येंद्र रंजन................. 29
अन्य
अनुसूचित जाति मोर्चा बैठक.. 4
अल्पसंख्यक मोर्चा रा.का. बैठक. 26

सम्पादक
çHkkr >k] lkln
सम्पादक मंडल
lR;iky
d- d- 'kek
lathò dekj flUgk
पृष्ठ संयोजन
/keUæ dk'ky
सम्पर्क
Mk- eqdthZ Lefr U;kl
ihih&66] lqcze.;e Hkkjrh ekxZ
ubZ fnYyh&110003
Qksu ua- +91¼11½&23381428
QSDl % +91¼11½&23387887
lnL;rk gsrq % +91¼11½&23005700
सदस्यता शुल्क
okf"kZd 100#- | f=okf"kZd 250#-
e-mail address
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। : सम्पादक – प्रभात झा

{ *मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसका अहम्।* }

सौ दिन में झूठ ही झूठ तो आगे क्या होगा!

कांग्रेसनीत यूपीए सरकार के सौ दिन बीत गए।

वादा किया था प्रधानमंत्री यूपीए सरकार ने–

''हम सौ दिन के भीतर आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेंगे।''

देशवासियों, आप स्वयं विचार करें, क्या देश की आंतरिक व्यवस्था सुधरी है? उल्टे माओवाद और नक्सलवाद निरंतर चुनौती बन रहा है। कांग्रेस शासित राज्यों की हालत दयनीय है। स्वयं दिल्ली में सरेराह आम नागरिकों की जिंदगी खतरे में है। पुलिस व्यवस्था में सुधार के दावे खोखले साबित हुए।

सौ दिन के भीतर महंगाई पर काबू पाने की बात यूपीए सरकार द्वारा कही गई थी, क्या हुआ?

देशवासियों के सामने संकट का पहाड़ टूट गया है। 'महंगाई' मौत की तरह कहर बरपा रही है। दाम नीचे आने का नाम नहीं ले रहे हैं। दाल के 'दाम' कफन की कीमत से भी ऊपर चला गया है। 'सब्जियां' मिठाई की तरह उत्सवी सामग्री हो गई हैं। सरकारी अस्पतालों तक में भोजन दुश्वार हो रहा है। महंगाई ने भारत की 70 फीसदी जनता के घर को निचोड़ दिया है। चार माह बीत गए, नियंत्रण का नाम नहीं, उल्टे देश के वित्तमंत्री, कृषिमंत्री यह कहते हैं कि अभी तो कीमतें और बढ़ेंगी। आखिर यह कैसा आलम है? क्या यूपीए की सरकार ने सौ दिन में जनता को मौत देने का वादा किया था?

आतंकवाद पर नियंत्रण का वादा भी सौ दिन के भीतर ही था।

कांग्रेसनीत यूपीए सरकार ने आतंकवाद के मसले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया। वार्ता में भारत की भद्द पिटवा दी। प्रधानमंत्री ने स्वयं भारत की विदेश नीति को गहरा धक्का पहुंचाया। हमारे गत पांच–छह वर्षों के नरम रूख ने पाकिस्तान के हौसले मजबूत किए हैं। 26/11 की आतंकी घटना से सबक लेने के बजाए सफाई देते फिर रहे हैं। हमारे कदम की जगहंसाई हो रही है।

सौ दिन के भीतर कांग्रेसनीत यूपीए सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का वादा भी कर रही थी।

क्या हुआ? ढाक के तीन पात। जस की तस। आर्थिक संकट और गहराता जा रहा है। प्रस्तुत बजट में पैसा कहां से आएगा और घाटा कैसे पूरा होगा इसकी चर्चा कहीं नहीं है। आंकड़ों की जुगाली से देश को दिलासा देने का प्रयास किया गया है।

महिला आरक्षण लागू करने की बात सौ दिन के भीतर कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने कही। पर इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ाया गया।

गंगा से शुरूआत कर अन्य नदियों की सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए स्वैच्छिक राष्ट्रीय युवा कोर के गठन की बात कही गई। इस दिशा में किसी भी प्रकार की पहल नहीं।

सौ दिन के भीतर पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता विकास पर फोकस के लिए एक सार्वजनिक डाटा नीति तैयार करने की बात मात्र जनता की भ्रमित करने वाला कदम है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की पारदर्शिता और जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए एक सामाजिक लेखा परीक्षा लागू करने की

बात कही गई। लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया।

कांग्रेसनीत यूपीए सरकार ने कहा कि हम नियमित आधार पर कार्य निष्पादन देखभाल तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन के लिए तंत्र स्थापित करेंगे। सौ दिन बीत गए पर कुछ भी नहीं किया गया।

अंत में कहा गया कि वित्त समावेश के लिए संपर्क इकाइयों के रूप में कार्य हेतु बैंकों तथा डाकघरों में व्यापक सुधार किया जायेगा। यह कार्य भी सौ दिन के भीतर करने को कहा गया था। सौ दिन बीत गए पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि जिसके आधार पर यह कहा जाए कि बैंकों तथा डाकघरों में व्यापक सुधार होगा।

इस तरह ऐसे दस कार्यों के बारे में कहा गया कि सौ दिन के भीतर प्राथमिकता से किया जाएगा। ये कार्य तो करना दूर, उल्टे आम नागरिकों की जिंदगी इन सौ दिनों में बेहद मुश्किल हुई है। सौ दिन की प्राथमिकताओं का यह हश्र देखकर आगामी पौने पांच वर्षों की उम्मीद पर स्वतः पानी फिर जाता है।

जनता की नजरों में कांग्रेस नीत–यूपीए सरकार सौ दिन की कसौटी पर पूरी तरह असफल है। ■

साभार : नई दुनिया

भाजपा को सर्वस्पर्शी संगठन बनाने का संकल्प

भारतीय जनता पार्टी, "अनुसूचित जाति मोर्चा" की ओर से समय लगानेवाले कार्यकर्ताओं, प्रदेश प्रभारियों एवं नवीन सदस्यता अभियान के लिए विचार–विमर्श हेतु आवश्यक बैठक दिनांक 3 अगस्त, 2009 समय प्रातः 11.00 बजे 11, अशोक रोड, भाजपा मुख्यालय, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। बैठक में श्री रामलाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) एवं श्री बाल आपटे जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा, सदस्यता प्रमुख का मार्गदर्शन मिला।

बैठक की अध्यक्षता आदरणीय डा. सत्यनारायण जटिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति मोर्चा व पूर्व केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार ने की तथा मंच संचालन श्री कैलाश सांकला, राष्ट्रीय महामंत्री अनुसूचित जाति मोर्चा भाजपा ने किया।

भाजपा का नवीन प्राथमिक सदस्यता अभियान 6 जुलाई, 2009 से प्रारंभ हो गया है। इस प्राथमिक सदस्यता अभियान में अनुसूचित जाति में भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक सदस्य बने तथा संगठन विस्तार के लिए समय देने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाई जाए।

यह निर्णय अनुसूचित जाति मोर्चा आदि की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 18–19 जुलाई, 2009 को 11, अशोक रोड, नई दिल्ली में लिया गया। सदस्यता अभियान हेतु विशेष कार्यक्रम तय कर जिला, मंडल स्तर पर समय लगाने वाले कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर 7 दिनों के लिए विभिन्न प्रदेशों में सहयोग हेतु भेजने पर चर्चा हुई। सदस्यता अभियान हेतु अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों एवं पदाधिकारिों के साथ विचार विर्मश के लिए दायित्ववान कार्यकर्ता निश्चित कर नियुक्त किए गए जिससे कि अनुसूचित जाति के मतों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति अनुसूचित जाति मोर्चा के काम को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।

यह सभी कार्यकर्ता विभिन्न प्रदेशों में अनुसूचित बस्तियों में स्थानीय कार्यकर्ताओं के सहयोग से संगठन विस्तार हेतु सदस्यता अभियान में अग्रणी भूमिका निभाएंगे।

अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा देश में 100–125 दायित्ववान कार्यकर्ताओं को संगठन विस्तार के लिए अधिक समय देने वाले कुशल कार्यकर्ताओं की टीम बनाने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

मोर्चा ने पार्टी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सदैव पूरी निष्ठा से काम किया है। डा. जटिया ने कहा कि देश में अनुसूचित जाति की 17 प्रतिशत आबादी है। मोर्चा इस जाति के सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय के लिए सदैव संघर्षशील रहा है। और आगे भी रहेगा। आगामी विभिन्न राज्यों में क्रमशः झारखण्ड, हरियाणा, महाराष्ट्र व अरूणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भारी सफलता के लिए अभी से जुट जाए तथा भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को मुख्य स्थान दिलाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसकी पूर्ति के लिए पार्टी कार्यकर्ता तन–मन और धन से काम करें।

बैठक में मुख्यरूप से उपस्थित हुए श्री कैलाश मेघवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रभारी अनुसूचित जाति मोर्चा, श्री विजय सोनकर शास्त्री, श्री रमेशचन्द्र रत्न, श्री नारायण सिंह केसरी, श्री चुन्नी लाल रतवाया, राष्ट्रीय सचिव में श्री कृष्णा चौधरी, श्री राजेश बग्गा, सभी कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग जिसमें श्री मदनलाल सांकला, श्री रामचन्द्र चावरिया, श्री सुरेश गौतम, श्री सुरजभाल कटारिया, चौ. चांदराम, श्री जगपाल मंडोत, श्री रामनिवास नगोरा, श्री शांत प्रकाश, डा. आजाद सिंह चाहर, श्रीमती पूर्णिमा विद्यार्थी, निगम पार्षद श्री श्यामलाल मोरवाल, चेयरमेन, स.प.जोन, श्री गजानंद, श्री जयदेव बोरिया, श्री सुंदरलाल, श्री राजेन्द्र राठौर, श्री पूर्णचन्द्र खन्ना, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री किशन पाल केन आदि।■

हमारा हिन्दुत्व राजनैतिक नारा नहीं यह भारत की प्रकृति में है : मोहन भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघचालक श्री मोहन भागवत से टाइम्स आफ इण्डिया के श्री अर्णव गोस्वामी ने एक विशेष साक्षात्कार किया, जिसे उक्त पत्र ने 18 अगस्त 2009 को संस्करण में प्रकाशित किया। हम यहां उस साक्षात्कार का भावानुवाद अपने पाठकों के लिए प्रकाशित कर रहे हैं।

⏭ ***जब आपने सरसंघचालक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यभार संभाला तो आपने परिवर्तन पर जोर दिया था। आपने कहा था कि कोई भी संगठन इतनी तेजी से बदलाव नहीं कर पाता है जितनी शीघ्रता से हम कर पाते हैं और हम अपने नेताओं में भी परिवर्तन ला सकते हैं। क्या आप महसूस करते हैं कि इस वर्ष के चुनाव परिणामों से न केवल भाजपा में, बल्कि रा.स्व.सं. में भी यह आवश्यकता खड़ी हो गई है?***

रा.स्व.सं. के चरित्र में ही परिवर्तन का भाव भरा है। अतः हम परिवर्तन करते रहते हैं। हमने 1939 में अपनी प्रार्थना में परिवर्तन किया, परन्तु टिप्पणी यह होती रही कि रा.स्व.सं. बदल नहीं रहा है, जिसका मैंने जवाब दिया था। हमारा संगठन परिवर्तन के लिए सर्वाधिक तैयार रहता है। हां, कुछ चीजें होती हैं जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, जैसे जो हमारा मूलाधार है। रा.स्व.सं. में, ''हिन्दुस्तान हिन्दू राष्ट्र है''– इस मूलाधार को छोड़कर हम सब कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। परन्तु हमारे परिवर्तन करने का एक विशेष ढंग रहता है। पहले हम आम सहमति बनाते हैं और जब आम सहमति बन जाती है तो हम तुरंत बदलाव ले आते हैं।

⏭ ***उदाहरण के लिए 2004 के चुनाव में रा.स्व.सं ने कहा था कि भाजपा की हार का कारण 'हिन्दुत्व' विचारधारा को पीछे छोड़ देना था। वाजपेयी जी ने हार के कारणों में एक कारण गुजरात दंगों का बताया था, जिससे पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी। क्या देश के लोगों ने फिर एक बार उस 'राजनैतिक हिन्दुत्व ब्रांड' को खारिज नहीं कर दिया है?***

उस पर तो राजनैतिक पार्टी को विचार करना होगा। हमारा हिन्दुत्व कोई 'ब्रांड' नहीं है। हमारा हिन्दुत्व तो विविधता में एकता, कृतज्ञता, संयम, सरलता जैसे मूल्यों पर आधारित है। ऐसे ही मूल्य हिन्दुत्व होते हैं। इसका राजनीति से कोई सम्बंध न होकर आपके जीवन की हर बात से सम्बंध रहता है। इसमें किसी धर्म या जाति विशेष का कोई सम्बंध नहीं है।

⏭ ***क्या आप इस बात को नहीं मानते हैं कि आज हिन्दुत्व देश में बहुत हद तक राजनैतिक प्रसंग में ही समझा जाता है। आप मानते हैं कि यह एक जीवनशैली है, परन्तु क्या आप यह नहीं समझते कि बिना जीवन के हिन्दुत्व किस प्रकार से राजनैतिक नारे के रूप में काम कर सकता है?***

राजनैतिक नारे के रूप में, हिन्दुत्व कैसे काम करता है या नहीं करता है, यह बात बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। आप किस प्रकार से नारे को पेश करते हैं और उस समय की किस प्रकार की परिस्थिति होती है, इससे बहुत कुछ अंतर पड़ जाता है। कभी यह काम करता है, कभी नहीं भी करता है। परन्तु इसके कारण अलग–अलग रहते हैं। परन्तु हमारा हिन्दुत्व कोई राजनैतिक नारा या राजनैतिक विचारधारा नहीं है। हिन्दुत्व तो भारत की प्रकृति में है, यह भारत का स्वतंत्र अस्तित्व है, जो विविधता में एकता का प्रतीक है, जिसकी हर बात में आपको झलक दिखाई पड़ती है और यह सर्वोत्कृष्ट है।

⏭ ***परन्तु भाजपा में एक काफी बड़ा वर्ग है, जो बड़े दुराग्रहपूर्ण ढंग से इसकी प्रस्तुति और व्याख्या करता है। आज हिन्दुत्व को इसकी राजनैतिक व्याख्या और राजनैतिक असहिष्णुता के रूप में उपयोग होते देखा जाता है। क्या आप इस बात से इंकार करेंगे कि भाजपा राजनैतिक रूप से हिन्दुत्व का उपयोग कर रही है?***

मैं कह चुका हूं कि यह बात तो भाजपा के सोचने की

है। हमारा काम तो यह है कि हम सीधे–सीधे समाज के पास पहुंचते है। हमारे काम में कभी भी इस प्रकार की अवधारणा नहीं रहती है। अभी कुछ समय पूर्व नागपुर के एक मुस्लिम विद्वान के साथ मेरी भेंट हुई। हमने विचारों का आदान प्रदान किया। उनके दिमाग में जरा भी हिन्दुत्व के बारे में भ्रम नहीं था। अतः किसी भी राजनैतिक पार्टी को इसी विशेष बात पर विचार करना चाहिए।

⏭ ***क्या आप मानते हैं कि भाजपा ने हिन्दुत्व को छोड़ दिया है। भाजपा आज कुछ मुद्दे जैसे रामजन्मभूमि, धारा–370 तथा समान नागरिक संहिता का पर्याय बन गई है। यह राजनैतिक हिन्दुत्व की संकीर्ण समझ लगती है। क्या आप मानते हैं कि शायद हिन्दुत्व की व्याख्या उतनी वैध नहीं रह गई है और शायद आजकल देश के लोगों के लिए इसकी उतनी प्रासंगिकता नहीं रह गई है?***

ये सभी मुद्दे, जैसे अनुच्छेद 370 का मुद्दा हिन्दुत्व से सम्बन्धित नहीं है। इसका सम्बंध तो हमारी मातृभूमि, हमारे देश की एकता से है। हम सब एक हैं। अतः नियम अलग–अलग है। रामजन्मभूमि मुद्दे के मामले में विदेशी आक्रामकों ने मन्दिर ध्वस्त किया था। अब हम स्वतंत्र है, इसलिए हमें अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक को बहाल करना होगा। इसका सम्बंध हिन्दू, मुस्लिम आदि से कुछ भी नहीं है। ये तो हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान है। इसीलिए मैं कहता हूं, हमारे मूल्य भारत के लिए विशेष हैं, जो भारत के मुस्लिम के लिए भी हैं, भारत के ईसाइयों के लिए भी हैं और भारत के तथाकथित हिन्दुओं के लिए भी हैं। सभी हमारे उत्तराधिकारी उसी विशेष संस्कृति की देन हैं।

⏭ ***परन्तु ठीक इसी समझ के कारण लोगों का कहना है कि भाजपा अपनी ही हठधर्मिता के जाल में फंस गई है। लोगों का कहना कि यही कारण है कि अन्य पार्टियां तो आगे बढ़ गई हैं जबकि भाजपा वहीं खड़ी रह गई है। आम धारणा यही है कि यदि भाजपा को आगे बढ़ना है तो उसमें बदलाव लाना जरूरी है।***

यह बात तो भाजपा के सोचने की है। आप भाजपा के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। मैं तो रा.स्व.सं. का सरसंघचालक हूं। यह तो स्वयं भाजपा को सोचना है कि वह हिन्दुत्व की व्याख्या किस प्रकार करती है।

⏭ ***चुनाव परिणामों के बाद आप और रा.स्व.सं. के दो बड़े नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी के निवास पर मिलने गए थे। क्या आपने आडवाणीजी को नेतृत्व करते रहने को कहा था?***

आपकी सूचना के लिए बता दूं कि मैं तब उनमें नहीं था, मैं अपने काम से दौरे पर था। आप मेरा दौरा–कार्यक्रम देख सकते हैं। आडवाणीजी ने इस्तीफा दिया था और तब तीन लोग उनसे मिलने गए थे। वह भाजपा नेता हैं, इसलिए वे उनसे मिलने गए थे।

⏭ ***क्या रा.स्व.सं. के नेताओं ने उनसे इस्तीफा न देने की बात कही थी?***

नहीं, तब हमने आडवाणी जी से कुछ नहीं कहा था। उन्होंने स्वयं ही कहा था कि ये उनका अपना निर्णय था।

⏭ ***आप कह रहे हैं कि यह आडवाणी जी का स्वयं का निर्णय था। क्या ऐसा नहीं था कि रा.स्व.सं. के नेता उनसे मिले और कहा कि वे बने रहें? इस प्रकार की रिपोर्टिंग हुई थी।***

दोनों ही निर्णय उनके अपने ही थे।

⏭ ***जिस प्रकार से भाजपा ने चुनाव अभियान चलाया उस बारे में उसकी आलोचना हुई है। रा.स्व.सं. की पत्रिकाओं में लिखा है कि राजनीतिक लड़ाई जमीनी स्तर से होती है, न कि एयरकंडीशन कमरों से। आरोप यह है कि आडवाणी जी ने चुनावी लड़ाई नगरों के ढंग से की गई। क्या आप इस आलोचना से सहमत हैं?***

रा.स्व.सं. के प्रकाशनों में बहुत से लोग अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। औपचारिक वक्तव्य केवल सरसंघचालक, सरकार्यवाह और प्रेस से मिलने के लिए नामित अन्य छह प्रवक्ता ही देते हैं। परन्तु हमारे स्वयंसेवक स्वतंत्र हैं और वे अपने बहुत से विचार रख सकते हैं।

⏭ ***तो, आप क्या मानते हैं?***

मैं कोई राजनीति का विशेषज्ञ नहीं हूं। हमारे अनेक स्वयंसेवक राजनीति में हैं और भाजपा में हैं। उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए और यदि उन्हें इन आलोचनाओं मे कोई सच्चाई नजर आती है तो उन्हें इस पर टिप्पणी करनी चाहिए।

⏭ ***भागवतजी, आप निरंतर भाजपा से दूरी बनाए रखने की बात करते हैं, जबकि रा.स्व.संघ और भाजपा के बीच के सम्बंधों की बात एक खुला तथ्य है।***

बहुत से स्वयंसेवक भाजपा में है और हम इस बात से इंकार नहीं करते हैं। हां, भाजपा में हमारे स्वयंसेवक पार्टी के उच्च स्थानों में हैं, परन्तु भाजपा पार्टी एक अलग राजनैतिक संगठन है।

⏭ ***अगले 5 वर्षों में आप क्या कुछ देखते हैं?***

इसका निर्णय उन्हें करना है। यदि वे आते हैं और हमारा सुझाव मांगते है तो हम उन्हें सुझाव देंगे।

⏭ ***आपका सुझाव क्या होगा?***

जब तक वे मुझसे सुझाव नहीं मांगते तब तक मैं कोई सुझाव नहीं देता।

⏭ ***यदि मैं गलत नहीं हूं तो हेडगेवारजी के बाद आप सबसे कम आयु के रा.स्व.सं. के सरसंघचालक बने हैं। क्या आप इस बात से खुश है कि भाजपा की प्रथम कतार में 70–85 वर्ष की आयु के लोगों और दूसरी कतार में 60–75 वर्ष की आयु के लोगों की भिन्नता पाई जाती है?***

इसके बारे में भाजपा को निर्णय लेना है। यह सवाल हमारे सोचने का नहीं है। उन्हें अपनी पार्टी का प्रबंध करना है। यह सार्वभौमिक नियम है कि पुरानी पीढ़ी के स्थान पर युवा पीढ़ी आती है। परन्तु कब और कहां– यह कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में भाजपा को तय करना है। इस समय वर्तमान स्थिति एकदम इसके उलट है। अब पीढ़ी पुरानी हो चुकी है। उन्हें ही अपनी पार्टी में युवाओं की भागीदारी का निर्णय लेना है। भाजपा के नियम–कायदे मौजुद हैं।

⏭ ***परन्तु परिवर्तन आवश्यक है ही?***

हां, परिवर्तन तो हर जगह आवश्यक है, केवल भाजपा में ही नहीं।

⏭ ***क्या आप समझते हैं कि यह परिवर्तन अगले आम चुनावों तक रोका जा सकता है?***

इसका आकलन तो भाजपा को करना होगा।

⏭ ***परन्तु, आपकी राय है कि परिवर्तन आवश्यक है। आप मानते है कि भाजपा को अगले आम चुनावों में युवा नेतृत्व की जरूरत होगी?***

हां, परन्तु, कब और कैसे यह तो उनका विशेषाधिकार है।

⏭ ***क्या आपने यह संदेश आडवाणी जी तक पहुंचा दिया?***

मैं तो यह बात 2003 से कहता आ रहा हूं। जब कभी वे हमसे पूछते हैं कि हमारी पार्टी कैसी हो तो हम कहते हैं कि आपके पास पर्याप्त संख्या में युवा कार्यकर्ता हैं। धीरे–धीरे उन्हें आगे बढ़ाइए।

⏭ ***क्या ये पार्टी के शिखर स्तर पर हो या सभी स्तरों पर हों?***

परिवर्तन सभी स्तरों पर होता है। हर स्तर पर औसत आयु समूह होता है। उस औसत को कायम रखा जाए।

⏭ ***यह औसत आयु समूह कितना हो?***

मैं राजनीति के बारे में नहीं जानता, परन्तु संघ में, मेरे स्तर पर हम औसत आयु समूह में 55–60 वर्ष की बात करते हैं।

⏭ ***तो आपके विचार में भाजपा के नए नेतृत्व में 55–60 वर्ष की आयु का होना चाहिए।***

मैं राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूं। राजनीतिक पार्टियों में आदर्श आयु समूह का निर्णय उन्हें करना है। मैं इसका आकलन करने वाला कौन होता हूं।

⏭ ***आप कहते रहे हैं कि भाजपा का अलग अस्तित्व है, परन्तु भाजपा के साथ आपके लम्बे समय से सम्बंध रहे हैं और भाजपा ने कहा है कि रा.स्व.सं. के साथ उसके अपने सम्बंधों पर गर्व है। आप भाजपा की राजनीति में सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। भाजपा में जो कुछ हो रहा है, उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं?***

मैं आपसे बड़ी खुली बात कर रहा हूं। अचानक ही, मेरे विचार में भाजपा को गहरा आघात पहुंचा है। अतः वह थोड़ी बहुत अस्थिर हो गई है। भाजपा में जो कुछ भी हुआ वह कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ। यह बात केवल मैं ही नहीं कह रहा बल्कि राष्ट्रीय कार्यसमिति में भी इस बात की अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप में हुई है। मैं जानता हूं कि भाजपा के सभी नेता इस स्थिति को बुरा समझ रहे हैं। उन्हें जल्द ही संतुलन बनाना होगा। यह कैसे हुआ, क्या गलती हुई, भाजपा को अपनी चिंतन बैठक में विचार करना होगा और मुझे विश्वास है कि वे करेंगे भी।

⏭ ***परन्तु, अब भाजपा में यह गुटबाजी बंद होनी चाहिए।***

हां, बहुत हो गया।

⏭ ***बिहार में पार्टी में आंतरिक कलह है, और अब राजस्थान में भी।***

इसका कारण कुछ असंतुलन और कुछ प्रक्रियाओं का अभाव रहा है। इस सबको दुरूस्त होना चाहिए। मैं उनसे नियमित रूप से मिलता हूं और उन्हें इस बारे में चिंता महसूस होती है। अतः वे इसे दुरूस्त करने के लिए उत्सुक हैं परन्तु उन्हें यह बहुत जल्दी करना चाहिए।

⏭ ***आप भाजपा में विशेष नेतृत्व की बात कर रहे हैं या सामान्य नेतृत्व की?***

मेरा तात्पर्य सामान्य नेतृत्व से है।

⏭ ***इन तीन स्थितियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तीन स्थितियां है। भाजपा में आतंरिक लोकतंत्र नहीं है, सर्वोच्च शिखर पर कमजोर नेतृत्व और सर्वोच्च नेतृत्व में गुटबाजी?***

मैंने भाजपा की आंतरिक स्थितियों पर विचार नहीं किया है, क्योंकि यह मेरा काम नहीं है। मैंने तो उनसे इकट्ठे बैठ कर समस्याओं का समाधान करने की बात कही है। पार्टी का एक मिशन है। उस मिशन को ध्यान में रखना चाहिए और विचार करना चाहिए कि गलती कहां हुई। मुझे राजनीति की वास्तविक दैनिक कार्यप्रणाली का पता नहीं है। उन्हें स्वयं ही इसका आकलन करना होगा।

⏭ ***भाजपा में राजनाथ जी के नेतृत्व पर आपके क्या विचार हैं? आपने भाजपा के कई नेताओं को देखा है। आपने भाजपा के उतार–चढ़ाव भी देखे हैं। कभी भी इतनी खुली गुटबाजी सामने नहीं आई जितनी अब आम चुनाव से पहले और बाद में देखने को मिल रही है। क्या सर्वोच्च नेतृत्व को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए?***

किसी एक व्यक्ति पर इस जिम्मेदारी को मानने की बजाए बेहतर होगा कि सभी नेतागण पार्टी की सामान्य स्थिति पर ध्यान दें। मैं नहीं समझता कि यह राजनाथ सिंह के कारण, आडवाणी जी के कारण या फिर इस आदमी या उस आदमी के कारण ऐसा कुछ हुआ हो। बात यह है कि पार्टी की सामान्य क्षमता प्रभावित हुई है और इसे दुरूस्त किया जाना चाहिए।

⏭ ***शिखर नेतृत्व में बहुत कुछ अंतर्कलह रहा है।***

उन्हें पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। कोई भी नेता केवल अपने बारे में ही नहीं सोच सकता है क्योंकि पार्टी सर्वोच्च होती है।

⏭ ***आप की आडवाणी जी से मुलाकात हुई। क्या आपने इस बैठक में आडवाणी जी से त्यागपत्र देने को कहा?***

मैंने आडवाणी जी से नहीं कहा। वह मेरे पास आए थे। वह मुझसे मिलना चाहते थे। उस दिन मैं नागपुर में नहीं था। मैंने कहा, मैं दिल्ली में हूं। उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने मुझसे एक घण्टे मिलने की बात कही। भोजन का समय था और हमने भोजन किया। उन्होंने यह सभी बातें बताई। मैंने उनसे कहा कि वह सोचें कि ऐसी स्थिति कैसे पैदा हुई। मैंने उनसे मतभेदों का समाधान करने को कहा और यह भी कहा कि किस प्रकार से पार्टी की छवि को सुधारने की व्यवस्था को कार्यान्वित करें क्योंकि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है। मैंने उनसे कहा कि सभी को मिलकर बैठना चाहिए और स्थिति की व्याख्या करनी चाहिए। व्यक्तिगत हितों को एक तरफ रखना चाहिए। वह व्यक्तिगत रूप से बहुत दुःखी थे और कहा कि ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं बनी। मैंने आडवाणी जी से कहा कि कोई तरीका निकालना चाहिए जिससे पार्टी फिर से पटरी पर वापस आए।

⏭ ***आप उनके लिए क्या भूमिका ठीक समझते हैं? आप आडवाणी जी को किस भूमिका में देखना चाहते हैं– एक बुद्धिमान परामर्शदाता के रूप में– एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो इस बदलाव में मार्ग निर्देशक का काम कर सके?***

वह बड़े सम्मानीय व्यक्ति हैं। यदि वह कार्यसमिति को कहेंगे तो निश्चित ही उनकी बात को माना चाएगा।

⏭ ***रा.स्व.सं. सभी स्तरों पर भाजपा में बदलाव चाहता है। भाजपा में कुछ लोग इस बारे में कुछ चिंतित हैं। आप विभिन्न स्तरों पर– राज्य स्तर, जिलास्तर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाशाली व्यक्तियों को लाना चाहते हैं। आप इस प्रमुख विपक्षी पार्टी पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। इस बदलाव की प्रक्रिया में आपकी क्या भूमिका होगी?***

⏭ हम भाजपा में अपने स्वयंसेवकों से पांच बातें कह सकते हैं। पहली बात कि विचारधारा के बारे में समुचित रूप से दृढ़ और स्पष्ट रहें। दूसरे, आपका सही कार्य प्रणाली रहनी चाहिए। जहां स्वयंसेवक लोग काम करते हैं, वहां आप अनेक शुभेच्छुओं के साथ अपना संवाद बनाए रखिए। आप उन लोगों से बातचीत करें, जो स्वयंसेवक नहीं है, परन्तु जो भाजपा की विचारधारा से सहमत हैं। उन्हें लगातार उनके साथ संवाद की व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। उनके साथ संवाद समाप्त नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात है कि आपका चरित्र अलग ही दिखाई पड़ना चाहिए। आखिरी बात यह है कि युवा पीढ़ी को आगे लाया जाए। यह बातें हैं जो हम भाजपा में अपने स्वयंसेवकों से कहता रहता हूं। भाजपा को एक पार्टी के रूप यह करना होगा। रा.स्व.सं. एक पार्टी के रूप में भाजपा का संचालन नहीं करता है। पार्टी को ही अपना रास्ता निकालना है। वे इससे सहमत होते हैं या नहीं होते हैं, वे इस बारे में स्वतंत्र हैं। परन्तु हमारे स्वयंसेवक सदैव हमारे हैं। हम उन्हें यह बताते रहते हैं।

⏭ ***क्या आप समझते हैं कि यदि रा.स्व.सं. अधिक राजनीतिक रूप से भागीदारी निभाए तो भाजपा इसका प्रतिरोध करेगी।?***

ऐसा नहीं होगा। मेरे विचार में भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। भाजपा में गैर–स्वयंसेवकों से भी हमारे सम्बंध अच्छे हैं।

⏭ ***मैं इस अवसर पर आपसे कुछ सीधे प्रश्न करना चाहूंगा। इस देश में 50 प्रतिशत से अधिक लोग 35 वर्ष की आयु से कम हैं। और मेरे विचार में 40 से कम आयु के लोग इससे भी अधिक है। क्या आप समझते हैं कि क्या ये लोग उन बातों को मानते हैं जो वरूण गांधी ने कहा। क्या आप समझते हैं कि वरूण गांधी ने जिस प्रकार के भाषण दिए, उसे युवा भारत के लोग स्वीकार कर सकते हैं?***

हम युवा लोगों के पास अपने हिन्दुत्व, देशभक्ति और सेवा के साथ जाते हैं। यही बातें युवा पीढ़ी में सर्वाधिक क्षमताएं रखती हैं और हमें उनसे बहुत अच्छा जवाब मिलता है। वरूण गांधी ने क्या कहा और वह क्या कहना चाहते थे, मैंने इसका अध्ययन नहीं किया है। मुझे केवल दो या तीन वाक्यों का ही पता है। मुझे प्रसंग के बारे में मालूम नहीं है। परन्तु, मैं उन एक–दो वाक्यों से सहमत नहीं हूं। मैं नहीं जानता कि ये वरूण गांधी ब्रांड क्या चीज है।

⏭ ***भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा?***

इसका निर्णय उन्हें करना है।

⏭ ***अगले भाजपा अध्यक्ष चार लोगों तक सीमित है– अरूण जेटली, वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज और नरेन्द्र मोदी। क्या पांचवा, छठा या सातवां अथवा आठवां भी हो सकता है?***

यह तो भाजपा पर निर्भर है। यदि भाजपा इन चार लोगों के पार भी देखती है तो मेरे विचार में लोगों का अभाव नहीं है। यदि भाजपा इन चार लोगों में से चयन करती है तो इनमें से कोई भी अध्यक्ष हो सकता है।

⏭ ***क्या प्रतिभा चार लोगों तक सीमित है?***

नहीं, 75 से 80 और लोग भी हो सकते हैं जिनमें नेता बनने की योग्यता है।

⏭ ***आपसे बातचीत कर बहुत खुशी हुई और आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से बात की।***

धन्यवाद!

साभार ■

महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरी भाजपा

& loknnkrk }kjk

महंगाई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि कांग्रेसनीत संप्रग सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। ''आम लोगों के साथ'' का वादा करने वाली कांग्रेस गत 6 सालों से लोगों के मुंह का निवाला छीनने में जुटी है। देशभर में हाहाकार मचा है। जनता महंगाई से परेशान है। ऐसे में भाजपा ने सशक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करते हुए 17 अगस्त को देशभर में महंगाई विरोधी सभा व रैलियों का आयोजन कर केन्द्र सरकार पर हमला बोला। हम यहां संक्षिप्त विवरण प्रकाशित कर रहे हैं:–

दिल्ली

बेलगाम मंहगाई से आम आदमी का जीना मुहाल : राजनाथ सिंह

भारतीय जनता पार्टी द्वारा 17 अगस्त को पूरे देश में मंहगाई विरोधी दिवस मनाने का जो आह्वान किया गया था, उसी के अंग के रूप में दिल्ली प्रदेश भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर विशाल धरना दिया। भाजपा के केन्द्रीय नेताओं में से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह और राज्य सभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली ने धरने को सम्बोधित किया और केन्द्र की यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों का खोखलापन रेखांकित किया। दिल्ली प्रदेश के नेताओं प्रदेश अध्यक्ष प्रो. ओम प्रकाश कोहली, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना, राष्ट्रीय उपाध्यक्षा डॉ. अनिता आर्य, राष्ट्रीय महामंत्री श्री थावरचंद गहलौत, मोर्चों के अध्यक्षों और प्रमुख पदाधिकारियों ने धरने में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं को सरकार की गलत आर्थिक नीतियों से अवगत कराया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार को एक अर्थशास्त्र का ज्ञाता प्रधानमंत्री चला रहा है, लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था संभलने का नाम नहीं ले रही। कृषि उत्पादन बढ़ नहीं पा रहा। उद्योग बंद हो रहे हैं। लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था अपनी आंतरिक ऊर्जा खो बैठी है। हाल ही में सरकार ने जो बजट पेश किया, वह दिशाहीन बजट था जिससे अर्थव्यवस्था को संभलने में मदद मिलने की आशा नहीं की जा सकती। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जैसी विकट मंहगाई आज आम आदमी को झेलनी पड़ रही है, वैसी पिछले अनेक दशकों में कभी भी अनुभव नहीं की गई। यूपीए की निकम्मी सरकार न नक्सलवाद को रोक पा रही है न आतंकवाद को और न मंहगाई को। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरत की चीजें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी और उनके दाम भी सस्ते थे। श्री राजनाथ सिंह ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मंहगाई को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाये तो भारतीय जनता पार्टी सरकार विरूद्ध देशव्यापी स्तर पर जबरदस्त आंदोलन खड़ा करेगी।

श्री अरूण जेटली ने अपने सम्बोधन में सवाल खड़ा किया कि मंदी और मंहगाई में क्या रिश्ता है। सरकार मंहगाई के लिए देशव्यापी मंदी को जिम्मेदार ठहरा रही है। मंदी के कारण बेरोजगारी का बढ़ना और उद्योगों का बंद होना तो समझ में आ सकता है, लेकिन मंहगाई के बढ़ने के लिए यह असल कारण नहीं हो सकता। असली कारण तो सरकार की आर्थिक मोर्चे पर दिशाहीनता है। जब तक सरकार अपनी नीतियों को आम आदमी के जीवन से नहीं जोड़ती तब तक मंदी पर नियंत्रण कर पाना कठिन होगा। उन्होंने कहा कि जनता आज मंहगाई के प्रश्न से जैसे उद्वेलित दिखाई पड़ती है वैसी आजादी के बाद शायद ही पहले कभी दिखाई पड़ी हो। उन्होंने सरकार से अपनी आर्थिक नीतियों की दिशा बदलने के लिए जोरदार मांग की।

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष प्रो. ओम प्रकाश कोहली ने प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार ने 100 दिन में जो वायदा पूरे करने का एजेंडा तय किया था, उसे पूरा करना तो दूर उलटे अनेक मामलों में सरकार पीछे हटी है। सरकार की नीतियां सम्पन्न वर्गों को सुविधाएं प्रदान करने की हैं और आम आदमी पर बोझ बढ़ता जा रहा है। किसान अनाज

उत्पादन में लाभ न देखकर जैविक ईंधन तैयार करने वाली कृषि की ओर मूड़ गया है। इससे अनाज उत्पादन में गिरावट आई है और अनाज तथा दालों के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। उन्होंने 80 दुकानों पर सस्ती दालों के बेचने के दिल्ली सरकार के कदम को ऊंट के मुंह में जीरे की संज्ञा दी और कहा कि इस प्रकार की नौटंकी से मंहगाई पर काबू नहीं पाया जा सकता।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा कि उसने राशन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। बीपीएल के कार्डधारकों को सस्ता राशन क्यों नहीं मुहैया कराया जा रहा है? दिल्ली को स्लम मुक्त करने और 10 हजार मकान बनाने की दिल्ली सरकार की घोषणा का मज़ाक उड़ाते हुए प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में लगभग 25 लाख लोग झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्र में और 50 लाख लोग अनधिकृत बस्तियों में रहते हैं। इतनी विशाल संख्या को देखते हुए 10 हजार मकान बनाने की घोषणा जनता से भद्दा मजाक है।

धरने में प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. नन्द किशोर गर्ग, पवन शर्मा, विशाखा शैलानी, महामंत्री रमेश बिधूड़ी, आर.पी. सिंह, प्रवेश वर्मा, संगठन महामंत्री श्री विजय शर्मा, प्रदेश मंत्री सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, रामचरण गुजराती, विरेन्द्र सचदेवा, कमलजीत सहरावत तथा प्रकोष्ठ प्रभारी श्री नरेन्द्र टंडन, नगर निगम में सदन के नेता श्री सुभाष आर्य, स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री रामकिशन सिंघल, स्थायी समिति की उपाध्यक्षा रजनी अब्बी तथा अन्य पार्षदों व विधायकों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त श्री विजेन्द्र गुप्ता, श्रीमती आरती मेहरा, श्री उदय शर्मा, श्री आदेश गुप्ता भी मंच पर उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश मंत्री एवं मीडिया प्रमुख श्री सतीश उपाध्याय ने किया।

प्रदेश के मोर्चाध्यक्षों ने भी धरने को सम्बोधित किया। महिला मोर्चा की अध्यक्षा सरिता चौधरी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष राज कुमार बल्लन, अल्पसंख्यक मोर्चाध्यक्ष आतिफ रशीद, अनुसूचित जाति मोर्चाध्यक्ष दुष्यंत गौतम और युवा मोर्चाध्यक्ष अनुज शर्मा ने मंहगाई के कारण जनता में तेजी से बढ़ रहे असंतोष की ओर सरकार का ध्यान खींचा और चेतावनी दी कि यदि सरकार इस समस्या का शीघ्र ठोस समाधान नहीं निकाल पाती तो उसके विरूद्ध जबरदस्त आंदोलन छेड़ा जाएगा। अंत में श्री प्रवेश वर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

धरने में बड़ी संख्या में महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्र के लाग विशेषरूप से किसानों ने भी भाग लिया।

उत्तर प्रदेश

महंगाई के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन

भाजपा की उत्तर प्रदेश ईकाई ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ 17 अगस्त को प्रदेश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा बढ़ती महंगाई के लिए केन्द्र की संप्रग और राज्य की बसपा सरकार को जिम्मेदार मानती है। बढ़ती महंगाई के बाबत भाजपा ने धरना–प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा।

लखनऊ में सुबह 11 बजे सैंकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर के साथ पैदल मार्च निकाला। बाराबंकी में कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दी। कानपुर देहात, फैजाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद सहित सभी जिलों में महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। लखनऊ में

भाजपा के प्रदेश मंत्री व विधायक सुरेश श्रीवास्तव और महानगर अध्यक्ष प्रदीप भार्गव के नेतृत्व में कार्यकर्ता जुलूस लेकर जैसे ही कैसरबाग बस अड्डे के पास पहुंचे, पुलिस ने बैरीकेटिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। प्रदेश उपाध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि महंगाई को लेकर त्रस्त जनता अब सीधी लड़ाई के मूड में है। सपा, बसपा के कांग्रेस समर्थन की पोल खुल गई है। अब भाजपा इस लड़ाई को लगातार लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्री होने के बावजूद प्रधानमंत्री डा.मनमोहन सिंह के नेतृत्व में मंदी और महंगाई एक साथ आई है। केंद्र को मंदी की चिंता है क्योंकि मंदी का प्रभाव बड़े घरानों पर पड़ता है लेकिन महंगाई सबका जीवन तबाह करती है। केंद्र सरकार महंगाई को लेकर गैर जिम्मेदार सिद्व हुई है।

भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 17 अगस्त को इलाहाबाद जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ आग उगली। नेताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण आम आदमी का जीवन कठिन हो गया है। महंगाई हर रोज बढ़ रही है, सूखे की मार ने किसानों को भुखमरी की कगार पर ला खड़ा किया है।भाजपा जिला इकाई की ओर से कचहरी पर आयोजित सभा में जुटे भाजपा नेताओं ने सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश की। केंद्र सरकार के सौ दिन होने के मौके पर केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर हुए इस प्रदर्शन के दौरान केंद्र के साथ ही राज्य सरकार की भी जमकर निंदा की गई।

जिलाध्यक्ष जनार्दन मिश्र की अध्यक्षता में हुई सभा में पूर्व मंत्री डॉ. नरेंद्र कुमार सिंह गौर, विधायक उदयभान करवरिया, पार्टी के पूर्व मंत्री विभूति नारायण सिंह, योगेश शुक्ल आदि प्रमुख नेताओं ने कहा कि महंगाई और सूखे की मार से कराह रही जनता के लिए न ही केंद्र सरकार ने कोई कदम उठाया

और न ही राज्य सरकार ने। केंद्र सौ दिन में रोजगार देने का वायदा पूरा नहीं कर पाई तो राज्य सरकार मुसलिम तुष्टिकरण में परेशान है। उन्होंने एससी–एसटी एक्ट का दुरुपयोग करने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित 10 सूत्री ज्ञापन डीएम को सौंपा।

महानगर के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष मनोज दुबे के नेतृत्व में सिविल लाइंस स्थित सुभाष चौक पर धरना–प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

बिहार

महंगाई के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन के तहत भाजपा की पटना ग्रामीण और महानगर इकाई ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय से जुलूस निकाला और आयकर गोलंबर होते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचे। जुलूस का नेतृत्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राधामोहन सिंह ने किया। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे।

राधामोहन सिंह ने कहा कि कांग्रेसनीत सरकार महंगाई पर नियंत्रण को लेकर गंभीर नहीं है। केंद्र सरकार के सौ दिनों के एजेंडे में महंगाई के न होने से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य भयंकर सूखे और बाढ़ की चपेट में है, लेकिन राहत देने की दिशा में कांग्रेस सरकार सुस्त पड़ी हुई है।

उड़ीसा

भाजपा की उड़ीसा प्रदेश इकाई ने पूरे राज्य में करोड़ों रूपयों के खनन घोटाले तथा आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किए। भाजपा के हजारों समर्थकों ने राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया।

भुवनेश्वर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राममंदिर चौराहे के निकट सड़कों पर नाकाबंदी की। जिला ईकाई अध्यक्ष रतिकांता दास के नेतृत्व में आयोजित रैली में अनेकों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भाजपा के नेता समीर मोहन्ती, विजयलक्ष्मी मिश्रा, सीमांतिनी जेना, दिलीप हरेकृष्णा खूंजिया, संतोष मोहन्ती, गोलक महापात्र, अमिया दास, लाला अशोक राय तथा अनेक लोगों ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पुजारी ने कहा कि यदि सरकार ने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो आने वाले दिनों में हमारा आंदोलन और भी तीव्र गति पकड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सतर्कता विभाग के पास तो खनन घोटाले के मामले में जांच पड़ताल करने के लिए आवश्यक सुविधाएं तक नहीं है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की जड़ें तो अब देश की सीमाओं को भी पार कर गई हैं। ये लंदन तक जा पहुंची हैं। वहां तो हमारे सतर्कता विभाग के गुप्तचर जांच का काम कर ही नहीं पाएंगे। सीबीआई के पास भी भ्रष्टाचार के मामलों पर ही छानबीन करने की विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचा मात्र है। उन्होंने साथ ही सरकार की इस बारे में भी गहरी आलोचना की कि वह आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को रोकने में भी असफल रही है जिससे आम आदमी बदहाली में जीने पर मजबूर हो गया है।

बरहमपुर शहा उड़ीसा का वाणिज्यिक केन्द्र है और यहां पर भी भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं ने शहर के अनेक स्थानों पर धरना देकर बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किए। पार्टी के नेताओं ने अपने भाषणों में केन्द्र की यूपीए सरकार और राज्य की बीजेडी सरकार को वर्तमान बदहाली की हालत के लिए जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने कहा कि प्रशासन को तुरंत ही इस विषय पर हस्तक्षेप कर सब्जियों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाना चाहिए। भाजपा रैली ने खनन घोटाले में भी सीबीआई जांच की मांग की। बंद के कारण शहर का जीवन अस्तव्यस्त रहा तथा बरहमपुर चैम्बर आफ कामर्स द्वारा दिए गए समर्थन के कारण दिन भर बाजार के अधिकांश हिस्से बंद पड़े रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कटक, पुरी, सम्बलपुर, राउरकेला, बालासुर और जयपुर आदि अन्य शहरों में भी विरोध मार्च संचालित किए।

आंध्र प्रदेश

संप्रग सरकार की गलत नीतियों के चलते बढ़ी महंगाई के विरोध में भाजपा, आंध्रप्रदेश ने विशाल रैली निकाली। जिसके दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं एम. वेंकैया नायडू, बंदारू दत्तात्रेय और राजीव प्रताप रूड़ी सहित 300 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं को आज उस समय हैदराबाद में एहतियात हिरासत में ले लिया गया जब वे रोजमर्रा के सामान की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए आंध्र प्रदेश विधानसभा की ओर

जा रहे थे।

भाजपा की आंध्र प्रदेश इकाई ने खाद्यान्नों, खाद्य तेल, चीनी और दाल आदि की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए 'चलो विधानसभा' कार्यक्रम आयोजित किया था।

श्री नायडू और राज्य भाजपा अध्यक्ष दत्तात्रेय के अलावा हिरासत में लिए गए अन्य वरिष्ठ नेताओं में श्री एन. इंद्रसेन रेड्डी आदि थे।

प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए विधानसभा की ओर रुख किया। हालांकि विधानसभा के चालू सत्र के दौरान हिमायतनगर के पास बड़ी संख्या में तैनात पुलिस बल ने उन्हें रोका और हिरासत में ले लिया।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हिरासत में लिए गए नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को नारायणगुडा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत वाईएमसीए मैदान ले जाया गया। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।

वरिष्ठ भाजपा नेता श्री वेंकैया नायडु ने केन्द्र को आवश्यक वस्तुओं की बेहद बढ़ती कीमतों के लिए दोषी ठहराया। भारतीय जनता पार्टी ने केन्द्र और राज्य सरकार से मांग की है कि वे आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए तुरंत कारगर कदम उठाएं।

बढ़ती कीमतें न रोक पाने के लिए केन्द्र में कांग्रेसी सरकार के 'लापरवाही' वाले रवैये की निंदा करते हुए भाजपा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार अपनी इस वर्तमान गहरी नींद से नहीं जागी तो पार्टी को अपना आंदोलन और भी तेज करना होगा।

श्री वेंकैया नायडु ने कहा कि सरकार जनहित के काम में लगे प्रतिनिधियों को गिरफ्तार कर लोगों के बढ़ते आक्रोश

को नहीं रोक सकती है। इससे पूर्व प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी तब से बढ़ती ही चली जा रही है जब से कांग्रेस सरकार ने राज्य और केन्द्र में सत्ता की डोर अपने हाथों में संभाल ली है।

उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य सरकारों के लिए आवश्यक है कि वह कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए उपाए करे, परन्तु केन्द्र को भी आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों पर नियंत्रण लगाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। उन्होंने याद दिलाया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के जमाने में उसने किस प्रकार से सूखे, साइक्लोन के बावजूद भी कीमतों पर नियंत्रण रखा था, बल्कि उस समय तो पोखरण II के परीक्षण के बाद विदेशी ताकतों ने देश पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बंडारू दत्तात्रेय, एन. इन्द्रसेन रेड्डी के. लक्ष्मण, चिंता साम्बा मूर्ति भी गिरफ्तार कर लिए गए। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया।

हरियाणा

भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का पुतला फूंका। पार्टी के वरिष्ठ नेता सर्वश्री सीताराम सिंगला और प्रदेश सचिव सुदेश यादव के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता केन्द्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने पार्टी कार्यालय से सोहना चौक पहुंचे। बाद में सोहना चौक पर भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि इस राज में बिजली– पानी गायब है। चोरी, डकैती, हत्याएं आम बात हो गई है।

भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और केन्द्र में राज्य सरकार सत्ता सुख में मस्त है। भाजपा नेताओं के आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा चुनाव से पहले झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त की है। सत्ता के बाद जनता को भुला दिया गया।

हाल ही में लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने ऐसा ही किया है। वायदा किया था कि जनता को सस्ती चीजें मिलेगी। चुनाव से पूर्व डीजल पेट्रोल के दाम गिरा दिए गए। लेकिन सत्ता प्राप्ति के बाद उन्हें पुनः बढ़ा दिया गया।

इस सर्वश्री कार्यक्रम में सीताराम सिंगला, सुदेश यादव के अलावा, जिला अध्यक्ष अरूण महेश्वरी, तेजपाल सिंह तंवर, जवाहर यादव, अनिल यादव सरपंच, कुलभूषण भारद्वाज रामकुमार यादव, सत्यप्रकाश कश्यप, यादराम जोया, रवि शंकर गौड़ रणबीर सिंह चौहान, बिहारी धर्म देव, सुमेर सिंह तंवर, पूर्व सरपंच ओमप्रकाश, सुरेश ततारपुर, जगदीश अम्बावता, कंवर लाल खटाना, परमिंद्र कटारिया, प्रेमपाल सलूजा, सुरेन्द्र, बाबूलाल गुप्ता, उमाकांत शर्मा आदि मौजूद थे।

मध्य प्रदेश

महंगाई का असल कारण राजनीतिक है, मौसमी नहीं : नरेन्द्र सिंह तोमर

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नरेन्द्र सिंह तोमर ने महंगाई के विरोध में आयोजित प्रदर्शन रैली का नेतृत्व किया। ग्वालियर के सेवा नगर से आयोजित महंगाई के चल समारोह की प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने अगुवाई की और तानसेन की मजार के आगे हजीरा पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में महंगाई ने महामारी के रूप में जन जीवन को बेहाल कर दिया है। महंगाई का कारण प्राकृतिक प्रतिकूलता नहीं अपितु केन्द्र में कांग्रेसनीत यूपीए सरकार की गलत आर्थिक नीतियां हैं। कांग्रेस की चुनावी चंदा खोरी ने देश को मुनाफाखोरों के हाथ सौंप दिया है। महंगाई का असल कारण भ्रष्टाचार, जखीराबाजी, मुनाफाखोरी है, जिसे रोकने में कांग्रेस अपराधिक रूप से विफल रही है। देश में महंगाई का असल कारण कांग्रेस की संस्थागत चंदा खोरी है। चंबल अंचल के मुरैना में आयोजित महंगाई विरोधी, धरना प्रदर्शन का भी नरेन्द्र सिंह तोमर ने नेतृत्व किया और कहा कि भाजपा महंगाई से जूझ रही जनता के साथ है। पूर्ववर्ती एनडीए सरकार ने जिस तरह देश में विकास दर दहाई में और मुद्रास्फीति इकाई में सबसे नीचे पहुंचा दी थी कांग्रेस ने पांच वर्षों में आर्थिक उपलब्धियों को मटियामेट कर दिया है। भिंड, दतिया में भी महंगाई के विरोध में धरना, प्रदर्शन आयोजित किया गया।

जनता पर महंगाई का निर्मम प्रहार कांग्रेस कठघरे में -माखन सिंह चौहान

भोपाल के न्यूमार्केट कम्युनिटी हाल परिसर के समक्ष भाजपा कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में विशाल जनसभा आयोजित की और धरना, प्रदर्शन कर रैली निकाली। बाद में गिरफ्तारियां दीं। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रदेश संगठन महामंत्री माखन सिंह चौहान ने कहा कि केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियां देश की जनता पर निर्मम प्रहार कर रही हैं। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड दी है। भगवत शरण माथुर, रामेश्वर शर्मा, उमाशंकर गुप्ता, आलोक शर्मा, सुरेन्द्र नाथ सिंह, सीमा सिंह, सरिता देशपांडे, कृष्णा गौर सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं ने धरना, प्रदर्शन को संबोधित किया और कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों की आलोचना की। बाद में माखन सिंह चौहान, भगवत शरण माथुर, रामेश्वर शर्मा, आलोक शर्मा, उमाशंकर गुप्ता, आलोक संजर, विश्वास सारंग, रामदयाल प्रजापति, रमेश शर्मा गुड्डू भैया, ओम यादव, गोरेलाल बड़गैया, सत्यार्थ अग्रवाल, आशा जैन, शैलेन्द्र शर्मा, गिरिराज किशोर, गौरीशंकर कौशल, अजय शर्मा, श्याम मोहन श्रीवास्तव, महेश शर्मा सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने धरना, प्रदर्शन में भाग लिया।

महंगाई विरोधी धरना प्रदर्शन के बाद न्यू मार्केट में रैली आयोजित की गई और कार्यकर्ताओं ने केन्द्र सरकार की महंगाई बढ़ाने वाली नीतियों के विरोध में माखन सिंह चौहान और भगवत शरण माथुर के नेतृत्व में गिरफ्तारी दी।

महंगाई के खिलाफ इंदौर में भारी सैलाब उमड़ा

इंदौर में महंगाई के खिलाफ इस बार ऐतिहासिक धरना, प्रदर्शन, रैली और उसके पूर्व अभूतपूर्व राजवाड़ा पर जनसभा आयोजित की गई जिसे सुमित्रा महाजन, सुदर्शन गुप्ता, मालिनी गौड़, गोपीकृष्ण नेमा, रमेश मेंदोला, बाबू सिंह रघुवंशी, महेन्द्र हार्डिया, कमाल भाई ने संबोधित किया और कांग्रेस की आर्थिक नीतियों की कड़े शब्दों में निंदा की।

जनसभा के बाद महंगाई को प्रदर्शित करने वाली झांकियों को प्रदर्शन, विधानसभावार किया गया जिन्हें देखने भारी भीड़ उमड़ी और इंदौर नगर में महंगाई विरोधी आंदोलन चर्चा का विषय बन गया। रैली में सभी मोर्चा, प्रकोष्ठों ने भाग लिया। विधानसभा क्रमांक एक की झांकी में गाजरमूली प्रदर्शित कर सुदर्शन गुप्ता ने महंगाई को आसमान छूते दिखाया। क्रमांक दो की झांकी में आम आदमी को फटेहाल दिखाया गया। क्रमांक तीन विधानसभा क्षेत्र की झांकी में ऊंट गाड़ी पर आम आदमी को फटेहाल होते और केन्द्र सरकार के मंत्रियों को ऐशोआराम के साथ काफी पीते दिखाया गया। क्रमांक चार में कार्यकर्ता तख्तियां लिए दाल आटे के चढ़ते भाव दिखा रहे थे। क्रमांक पांच में महंगाई को कमरतोड़ बताया गया। झांकियां शहर में घूमी जिसके साथ हजारों की संख्या में जनता चल रही थी। बाद में रैली के साथ सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और केन्द्र सरकार की जनविरोधी नीतियों को जनोन्मुखी बनाने की मांग की।

उजैन में धरना, प्रदर्शन देवास गेट चौराहा पर आयोजित किया गया। बाबूलाल जैन ने कहा कि कांग्रेस देश की जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है। कांग्रेस जब महंगाई कम करने की बात करती है, उसके दूसरे दिन महंगाई बढ़ जाती है। मुनाफाखोरी और कांग्रेस के बीच यह लुका छिपी का खेल है, जिसने आदमी की जिंदगी को दूभर बना दिया है। धरना, प्रदर्शन को लालसिंह राणावत, कान्हा राठौर, शिव नारायण जागीरदार, शांतिलाल, रामेश्वर अंखड, डॉ.प्रभुलाल जाटवा, रामेश्वर पाटीदार, किसन सिंह भटोलस, वीरेन्द्र कावडिया, मदनलाल सांखला ने संबोधित किया। बाद में रैली निकाली गयी।

प्याज लटकाने वाले आम जनता के दर्द से बेखबर-भूपेन्द्र सिंह

सागर में कीर्ति स्तंभ पर आयोजित महंगाई विरोधी धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री और सांसद भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि कांग्रेसी देश की जनता का आर्थिक शोषण होने पर खामोश है। प्याज महंगी होने पर गले में लटका रहे थे। आज तो उपभोक्ता वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। लगता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उद्योग घरानों से चंदा लिया था, अब उन्हें मुनाफा खोरी की छूट दे दी गयी है। इससे कांग्रेस की नीति और नीयत पर सवालिया निशान लग गया है। हवाला, सट्टा बाजार ने महंगाई को हवा दी है। तत्काल महंगाई पर रोक लगायी जाए। शैलैन्द्र जैन, प्रदीप लारिया, सुधीर यादव, विनोद तिवारी, राजेन्द्र सिंह, दाऊ सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी धरना प्रदर्शन को संबोधित किया। सागर में विशाल रैली भी आयोजित की गयी जिसमें हजारों गृहणियों ने भाग लिया और कांग्रेस की नीतियों की जमकर आलोचना की।

महंगाई का कांग्रेस से चोली दामन का रिश्ता है- चंद्रमणि त्रिपाठी

रीवा कलेक्टर कार्यालय के सामने आयोजित महंगाई विरोधी धरना, प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा कि महंगाई का कांग्रेस से चोली दामन का रिश्ता है। जब–जब कांग्रेस सत्ता में आती है, उसके साथ जमाखोर, जखीराबाज, शक्तिशाली हो जाते हैं। कांग्रेस उन्हें प्रश्रय देती है। महंगाई दहायी में पहुंच चुकी है। विकास दर घट रही है। केन्द्र सरकार आंकड़े परोस रही है। गरीब की थाली से दाल गायब हो गयी है।

पिछले पांच वर्षों में कांग्रेस ने कोरी चिंता की है। रोग बढ़ता ही गया ज्यों–ज्यों दवा की। कमलेश्वर सिंह ने धरना, प्रदर्शन का नेतृत्व किया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी धरना, प्रदर्शन में शामिल हुईं।

जबलपुर में ऐतिहासिक धरना संपन्न, कांग्रेस के राज में घोटाला-राकेश सिंह

जबलपुर में कलेक्टर कार्यालय परिसर घंटाघर के पास महंगाई विरोधी धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया जिसमें सांसद राकेश सिंह, पूर्व मंत्री बब्बू सिंह, शरद जैन, अंचल सोनकर, महापौर सुशीला सिंह, जबलपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष विशाल पचौरी, प्रभात साहू, धीरज पटैरिया, अनिल शर्मा सहित प्रमुख नेताओं ने भाग लिया और संबोधित किया। बाद में ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा नेताओं ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेसनीत केन्द्र की इस सरकार ने महंगाई के सभी रिकार्ड तोड़ दिये हैं। देश का अन्नदाता खुदकुशी करने को विवश हो रहे हैं। दर्जनों लोग खरबपति हो रहे हैं। देश की 80 प्रतिशत दौलत इनके यहां कैद हो गयी है। कांग्रेस इसे तरक्की बताकर देश की अस्सी प्रतिशत गरीब जनता के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। आयात और निर्यात कांग्रेसियों की जेबें भरने का जरिया बन गया है। दाल आयात घोटाला, गैर बासमती चांवल का निर्यात और शक्कर घोटाला ने कांग्रेस की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम की पोल खोल दी है। जनता इसे कमी माफ नहीं करेगी।

शिवपुरी में महंगाई के विरोध में आयोजित धरना प्रदर्शन का नेतृत्व रणवीर रावत ने किया। माधव चौक पर आयोजित सभा में ओमप्रकाश खटीक, देवेन्द्र जैन, माखन राठौर, प्रहलाद भारती ने संबोधित किया। श्योपुर में महंगाई विरोधी आंदोलन का नेतृत्व राधेश्याम रावत ने किया। गुना में राधेश्याम पारिख और अशोक नगर में आयोजित धरना प्रदर्शन का नेतृत्व सुभाष जैन ने किया। ■

महंगाई दर ने बनाया महंगाई का मजाक

आम उपभोक्ता भले ही अनाज, दाल और सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की महंगाई से परेशान है लेकिन सरकारी आंकड़ों की मानें तो महंगाई दर 1 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में घटकर शून्य से 1.74 फीसदी नीचे आ गई है जो तीन दशक में सबसे निचला स्तर है।

इससे पिछले सप्ताह महंगाई दर शून्य से 1.58 फीसदी नीचे और पिछले साल की इसी अवधि में यह 16 साल वर्ष के उच्च स्तर 12.91 फीसदी पर थी। यह लगातार नौवां सप्ताह है जब महंगाई दर शून्य से नीचे बनी हुई है। भले ही वार्षिक आधार पर अनाज के दाम 12 फीसदी, दालों के दाम 18 फीसदी और फल एवं सब्जियों के दाम 18.4 फीसदी तक बढ़ चुके हैं। समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान जौ, चना और ज्वार जैसी खाद्य वस्तुओं के दाम दो–दो फीसदी तक बढ़े, जबकि अरहर, मसाले और फल एवं सब्जियों की कीमतों में एक–एक फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान, आयातित खाद्य तेल के दाम 5 फीसदी तक बढ़े, जबकि गैर रिफाइंड तेल तीन फीसदी और चीनी एक फीसदी महंगी हुई। विनिर्मित वस्तुओं में बीयर एवं अल्कोहल के दाम 13 फीसदी तक बढ़े, ऊनी कपड़े की कीमत दो फीसदी, बेनजेन की कीमत 9 फीसदी और इलेक्ट्रोड्स की कीमत 22 फीसदी बढ़ी। हालांकि समीक्षाधीन सप्ताह में सीमेंट, लौह एवं इस्पात की कीमतों में मामूली गिरावट आई। इस दौरान विमान ईंधन की कीमत में दो फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। साल दर साल के आधार पर, दूध के दामों में करीब 4.8 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई जबकि मसाले की कीमत में करीब 4.2 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ■

और कितना रुलाएगी महंगाई?

t ;irh yky Hk.Mkjh

;कीनन देश में मानसून को बेरुखी से सूखे जैसे हालात ने लम्बे समय से कमरतोड़ महंगाई से जूझ रहे देश के लोगों की नींद उड़ा दी है। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री के महंगाई और बढ़ने सम्बंधी निराशाजनक बयानों के बाद सटोरियों और जमाखोरों के बढ़ते लालच के कारण अनेक खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी आई है।

निःसंदेह देश में आजादी के बाद कई बार सूखा पड़ा और उसका महंगाई पर असर भी दिखाई दिया लेकिन इस बार भारतीय मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों की खामियों, लापरवाही और लचर नीतियों ने महंगाई को बेलगाम कर दिया है। साफ है कि कृषि सुधार मोर्चे पर देश बहुत पीछे है। आजादी के कुछ वर्षों बाद तक तो विभिन्न खाद्य पदार्थ संतुलित मात्रा में उत्पादित किए जाते रहे, किन्तु पिछले दो–तीन दशकों से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में गलत नीतियों का खामियाजा भारी महंगाई के रूप में जनता को भुगतना पड़ रहा है।

पहली हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया था और यह नीति लगातार जारी है। फिर भी गेहूं एवं चावल का लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तिलहनों और दलहनों का उत्पादन लगातार उपेक्षित रहा है। वस्तुतः हमारी दलहन और तिलहन नीति इन फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को आर्थिक तौर पर प्रोत्साहित करने में विफल रही है।

इस समय दालों, खाद्य तेलों, चीनी और चावल के मूल्यों से लोग त्राहि–त्राहि कर रहे हैं। महंगाई का सबसे बड़ा कारण आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन नहीं हो पाना है। महंगाई का दूसरा सबसे बड़ा कारण आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन नहीं हो पाना है। महंगाई का दूसरा सबसे बड़ा कारण सरकार की ऐसी त्रुटिपूर्ण नीति भी है जिसके तहत उनका समय पर उपयुक्त आयात और उपयुक्त वितरण नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि उत्पादन और आपूर्ति की विसंगति के कारण दालों की कीमतें आसमान छू रही हैं। पिछले एक साल में दालों के दाम

दोगुने हो गए हैं। पिछले पंद्रह–बीस वर्षों में दालों के उत्पादन में वृद्धि नगण्य रही है। पिछले चार वर्ष से हम प्रतिवर्ष लगभग 20–25 हजार करोड़ रूपए की दाल आयात करते हैं। खाद्य तेल उत्पादन के मामले में भी हमारी यही स्थिति है। खाद्य तेल के संकट से देश को चिंतारहित करने के लिए 1986 में खाद्य तेल पर राजीव गांधी टेक्नोलॉजी मिशन गठित किया गया था। इसके तहत 1993 तक देश को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जाना था। लेकिन इस मिशन की सिफारिशों पर यथेष्ट रूप से अमल ही नहीं किया गया।

निःसंदेह देश में आजादी के बाद कई बार सूखा पड़ा और उसका महंगाई पर असर भी दिखाई दिया लेकिन इस बार भारतीय मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों की खामियों, लापरवाही और लचर नीतियों ने महंगाई को बेलगाम कर दिया है। साफ है कि कृषि सुधार मोर्चे पर देश बहुत पीछे है।

देश में दालों और खाद्य तेलों की तरह चीनी की कीमतें भी लगातार बढ़ती गई हैं। इसका प्रमुख कारण चीनी उत्पादन में भारी कमी आना रहा है। इसी तरह चावल के बुवाई क्षेत्रफल में भारी गिरावट का असर चावल की कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। इस तरह जिन खाद्य पदार्थों की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, उनसे सम्बन्धित अध्ययन बता रहे हैं कि हम खाद्य पदार्थों की खेती को संतुलित रूप से प्रोत्साहित नहीं कर पाए हैं। हम किसानों के लिए न तो अच्छा बाजार तैयार कर पाए और न उन्हें अच्छी कीमत दिला पाए। धीरे–धीरे चीनी, दाल, चावल और खाद्य तेल जैसे जरूरी खाद्य पदार्थों के लिए हमारी आयात निर्भरता बढ़ती गई है। यह पाया गया है कि जब–जब भारत जिन खाद्य पदार्थों का आयात करने लगता है तब–तब वैश्विक बाजार में उन खाद्य पदार्थों के दाम तेजी से बढ़ने लगते हैं और ऐसे में भारत को भारी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है।

देश को दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है, जिसमें पहले की गलतियां सुधारी जाएं। दूसरी हरित क्रांति में हर फसल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। खासतौर से देश में तिलहन–दलहन के उत्पादन के लिए एक समग्र नीति बनानी होगी। किसान अपने मन से फसल की बुआई न करके तर्कसंगतता के आधार पर बुआई करे और लाभकारी मूल्य प्राप्त करे। खाद्य पदार्थों के आवश्यक मात्रा में उत्पादन के लिए वास्तविक रूप में कृषि बजट बढ़ाना होगा। यदि वर्ष 2009–10 के बजट में

कृषि ऋण से जुड़े कदमों को छोड़ दें तो बजट में कृषि क्षेत्र को मौजूदा खाद्य पदार्थों के संकट से उबारने का कोई बड़ा कदम नहीं है। देश में सकल पूंजी निर्माण में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास करने होंगे। निजी निवेश बढ़ाने के लिए जरूरी होगा कि कृषक समुदाय के ज्यादातर लोगों के लिए जरूरी सस्ते ऋण तक आसान पहुंच बनाई जाए। अभी 73 फीसदी से ज्यादा किसान परिवार की पहुंच सस्ते ऋण के पारंपरिक स्रोत तक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा किसानों को संस्थागत क्रेडिट नेटवर्क से जोड़ना होगा। चूंकि अभी भंडारों के अभाव में बड़ी मात्रा में किसानों का अनाज सड़ जाता है और अनाज का भंडारण करने के लिए गोदाम उद्योग के पास पर्याप्त क्षमता नहीं है अतएव सरकार को गोदाम उद्योग को बुनियादी उद्योग का दर्जा देना चाहिए। इससे निजी निवेश की संभावनाएं भी तैयार होंगी।

महंगाई रोकने के लिए ऐसे दीर्घकालिक नीतिगण निर्णयों के साथ कुछ तात्कालिक त्वरित कदम भी उठाए जाने होंगे। राजीव गांधी सरकार ने 1987 में सूखे का मुकाबला करने के लिए जिस तरह से प्रशासनिक मशीनरी का युद्धस्तर पर उपयोग करके महंगाई की पीड़ा से आम लोगों को बचाया था, वैसा ही अभियान अब वर्ष 2009 में जरूरी है। इस समय जिन राज्यों में कृषि उत्पादों की लागत बढ़ गई है, उन राज्यों के लोगों को राहत देने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को विशेष इंतजाम करने चाहिए और ज्यादा सब्सिडी देनी चाहिए। सभी राज्यों में दाल, चावल, तेल, चीनी और अनाज पर अत्यावश्यक वस्तु कानून लागू करके खाद्य पदार्थों के बाजार को नियंत्रित करना चाहिए। खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सट्टेबाजी, जमाखोरी और कालाबाजारी को सख्त कानून से रोकना चाहिए। कुल मिलाकर खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि, खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि, खाद्य पदार्थों के वितरण में उपयुक्तता तथा खाद्य पदार्थों के समयानुकूल आवश्यक आयात से ही लोगों को महंगाई और भूख की पीड़ा से बचाया जा सकता है। देश की जनता को महंगाई से बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। ■

(लेखक विख्यात अर्थशास्त्री हैं)

जमाखोरी और कालाबाजारी ने किया है दाल में काला

nfonj 'keki ¼Ñf"k fo'k"kK½

भावना और अनुमान के आधार पर इस महंगाई को पैदा किया गया है। महंगाई की कोई ठोस वजह है ही नहीं। कहीं भी आपूर्ति और मांग का कोई संकट नहीं है। दाल के उत्पादन के मामले में पिछले साल और इस साल में कोई फर्क नहीं है। फिर भी दाल के भाव आसमान छू रहे हैं। सब्जियों के भाव भी बढ़ते ही जा रहे हैं। जबकि उत्पादन में गिरावट नहीं आई है। देश में गेहूं और चावल का 5.4 करोड़ टन अतिरिक्त भंडार है। तेजी से बढ़ती महंगाई के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जमाखोरी और कालाबाजारी है।

वायदा कारोबार भी महंगाई बढ़ाने के लिए काफी हद तक कसूरवार है। महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार भी सजग नहीं है। सरकार इसलिए भी सुस्त है कि महंगाई बढ़ने की वजह से जीडीपी के आंकड़ों में सुधार होता है। इससे सरकार को आर्थिक मोर्चे पर अपनी साख बचाने का अवसर मिलता है। सरकार यह कह रही है कि मंदी के बावजूद हमारी नीतियों की वजह से जीडीपी बेहतर रही। अब तो प्रधानमंत्री ने भी यह कह दिया है कि महंगाई के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए। इससे जमाखोरों का मनोबल और बढ़ेगा और साथ ही महंगाई भी साफ है कि सरकार कुछ करने वाली नहीं है। महंगाई को काबू में करने के लिए चावल, दाल और गेहूं पर भंडार की सीमा तय होनी चाहिए। जो भी इसका उल्लंघन करे उस पर राष्ट्रीय कानून लगाया जाए और उसे जेल भेजा जाए। वायदा कारोबार से कृषि उत्पादों को बाहर करना चाहिए। इन दो कदमों से जमाखोरी और कालाबबाजारी रुकेगी और महंगाई पर लगाम लगाई जा सकेगी।

कारोबारी नहीं सरकार है इस खेल की सूत्रधार : बनवारी लाल कंछल

महंगाई के लिए मेरी नजर में केवल और केवल केन्द्र सरकार ही दोषी है। व्यापारियों का इसमें कोई दोष नहीं है। मॉनसून को भी दोष देना ठीक नहीं है। वैसे भी मानसून तो चल रहा है और इस बार के सूखे का असर अभी तो देखने में आएगा नहीं। उसके लिए तो छह महीने लगेंगे जब फसल कट कर बाजारों में आएगी। सूखा पहले भी पड़ा पर इस कदर महंगाई कभी नहीं बढ़ी है। यहां तो महंगाई मुंह बाये खड़ी है और लोगों का जीना हराम कर रही है। उधर सरकार कह रही है कि सूखे के चलते आने वाले दिनों में चीजों के दाम बढ़ेंगे। अगर आने वाले दिनों में चीजों के दाम बढ़ेंगे तो अभी क्या हो रहा है। आपने देखा कैसे सफाई से आम चुनाव के ठीक पहले डीजल–पेट्रोल के दाम भी गिरा दिए गए और चीजों के दाम भी काबू में थे। रही बात कारोबारी को दोष देने की तो ये तो सबसे आसान है कि उसे दोष दो जो सामान बेचता हो, मुनाफाखोर ठहरा दो उसे। पर सच ये नहीं है।

असलियत तो ये है कि व्यापारी कभी महंगाई बढ़ाने की बात सोचता भी नहीं है। आज कुछ लोग जमाखोरी का आरोप आसानी से व्यापारी पर लगा देते हैं पर वो ये नहीं सोचते कि बड़े रिटेल स्टोर वाले क्या कर रहे हैं। असली जमाखोर तो रिटेल वाले लोग ही हैं जो कि थोक खरीदारी करके दाम बढ़ाते हैं और फिर अपना मुनाफा कमा उसे इन्हीं दिनों में स्कीम का लालच दे कर बेचते हैं। मेरी राय में महंगाई को रोकना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है और वह इससे मुंह नहीं मोड़ सकती है। सरकार अगर ऐसा करती हैं तो इसे जनता के साथ धोखा ही कहा जा सकता है। ■

सौ दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात

fl)kFk HkkfV;k

fd सी भी सरकार का पहले सौ दिन हनीमून पीरियड होता है। लेकिन यूपीए सरकार ने आते ही सौ दिनों का एजेंडा तैयार कर लिया था। एक के बाद एक हर मंत्रालय ने आनन–फानन में अपने सौ दिन का एजेंडा तैयार कर लिया। हर मंत्रालय इस तरह बल्लेबाजी कर रहा था मानो ट्वेंटी–ट्वेंटी का कोई मैच चल रहा है। सौ दिन का एजेंडा एक नया मंत्र बन चुका था। बहरहाल सौ दिन इस महीने के आखिर में खत्म हो रहे हैं और अब तक हम जो देख रहे हैं उसमें प्रदर्शन के मोर्चे पर यूपीए सरकार लड़खड़ाती ही नजर आ रही है। लोग निराश नजर आ रहे हैं। यह ठीक है कि इसके लिए सरकार के कदम ही दोषी नहीं हैं। आखिर खराब मानसून की उम्मीद किसने की थी। लेकिन मंत्रालयों का अब तक का कामकाज का जो रिकार्ड रहा है उस पर एक नजर डालना जरूरी है।

विदेश मंत्रालय- विदेश मंत्रालय के प्रदर्शन ने बेहद निराश किया है। एस. एम. कृष्णा को विदेश मंत्री बना कर प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि विदेश नीतियां पीएमओ से ही तय होंगी। कृष्णा मुख्यमंत्री और गवर्नर तक तो ठीक थे लेकिन इस हाई–प्रोफाइल पद के लिए उनके पास योग्यता नहीं थी। इसका पहला सबूत तब मिला, जब आस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर हमले हुए। इस मामले से निपटने के तरीकों के बारे में विदेश मंत्रालय में किसी को कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद शर्म–अल–शेख के मसले ने सिर उठा लिया। कृष्णा और उनके जूनियर मंत्री शशि थरूर और परनीत कौर ने तो अब तक कोई उम्मीद नहीं जगाई है।

पेट्रोलियम- पेट्रोल के दाम बढ़ाने के अलावा इस मंत्रालय को अलोकप्रियता के हमले कम ही झेलने पड़ते हैं। लेकिन अंबानी भाइयों के झगड़े में आखिरकार यह विवाद में फंस ही गया। पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा को झगड़े में पक्ष बनने के सवाल पर संसद में सफाई देनी पड़ी। देवड़ा दिग्गज राजनीतिज्ञ हो सकते हैं लेकिन मंत्रालय चलाने में वह अनुभवहीन साबित हुए हैं और अब तो वह दोनों अंबानी भाइयों के हमलों के बीच बुरी तरह फंस चुके हैं। हालांकि उनकी योग्यता की पूरी परीक्षा अभी बाकी है।

नागरिक उड्डयन- नागरिक उड्डयन मंत्रालय का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। राष्ट्रीय एयरलाइंस बुरी तरह घाटे में है और दूसरी निजी एयरलाइंस कंपनियों का भी प्रदर्शन काफी खराब है। नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल अब तक सबको दोषी ठहरा चुके हैं। प्रबंधन, कर्मचारियों, एटीएफ के दामों में बढ़ोतरी, मंदी सबको। लेकिन इससे उन्हें छुटकारा नहीं मिलने वाला। पटेल उन कुछ मंत्रियों में शामिल हैं, जिन्हें उनके मंत्रालय में ही बरकरार रखा गया। इसलिए उड्डयन क्षेत्र के संकट की जिम्मेदारी लेने से वह बच नहीं सकते। पिछले कुछ सालों में तो आपने एयरलाइंस कंपनियों की हड़ताल के बारे में तो नहीं ही सुना होगा। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि हर एयरलाइंस कंपनी हड़ताल की धमकी दे रही है। कुछ अनजान कारणों से वह प्रधानमंत्री के पसंदीदा बने हुए हैं और उन्हें बचाया भी जा रहा है। लेकिन आखिर वह कब तक बचेंगे।

> ***यूपीए सरकार ने आते ही सौ दिनों का एजेंडा तैयार कर लिया था। एक के बाद एक हर मंत्रालय ने आनन–फानन में अपने सौ दिन का एजेंडा तैयार कर लिया। हर मंत्रालय इस तरह बल्लेबाजी कर रहा था मानो ट्वेंटी–ट्वेंटी का कोई मैच चल रहा है। सौ दिन का एजेंडा एक नया मंत्र बन चुका था। बहरहाल सौ दिन इस महीने के आखिर में खत्म हो रहे हैं और अब तक हम जो देख रहे हैं उसमें प्रदर्शन के मोर्चे पर यूपीए सरकार लड़खड़ाती ही नजर आ रही है।***

कृषि मंत्रालय- शरद पवार अपनी छाया से ज्यादा कुछ नहीं रह गए हैं। एक समय में सब उनकी प्रशासनिक कौशल के कायल थे। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले वह प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। लेकिन पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद वह नरम पड़ गए हैं और अब उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं कांग्रेस विधानसभा चुनाव में उनसे साथ न छुड़ा ले। हालांकि क्रिकेट में अपनी व्यस्तता से वह अपनी इस तरह की चिंताओं से दूर रहते हैं। इस बीच देश का कृषि क्षेत्र संकट में आ चुका है और कई हिस्से सूखे की चपेट में हैं। यह साल उनके लिए चुनौती साबित होने वाला है।

स्वास्थ्य मंत्रालय- गुलाम नबी आजाद केन्द्र सरकार में पुराने खिलाड़ी रहे हैं। लेकिन स्वाइन फ्लू पर उनका भौंचक होना उनकी कलई खोल देता है। पहले उन्हें कुछ खास समझ नहीं आया लेकिन उसके बाद हवाईअड्डों पर थोड़ी बहुत व्यवस्था दिखी। पुणे में एक बच्ची की मौत के बाद मामला और बिगड़ गया। समझदारी दिखाने की बजाय उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे विवाद भड़क उठा। इस समय में जब एक सरकार प्रदर्शन में नाकाम रही है तो प्रधानमंत्री को कुछ हद तक इसका जिम्मा लेना चाहिए। कोई भी सरकार अपनी शुरूआत में इतने सारे विवादों से घिरी हो। यह एक खराब शुरूआत है और इससे जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में मुसीबतें और बढ़ेंगी। ■

मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बन गया कर्मकांडी आयोजन

प्रधानमंत्री के बुलावे पर देश के ज्यादातर मुख्यमंत्री दिल्ली आए। तीन दिन, कुछ न कुछ होता रहा। पर निकला क्या? जिन बड़े मुद्दों पर सम्मेलन में खासकर 17 और 18 अगस्त को बातें हुई, उनमें आम सहमति सिर्फ एक बड़े मुद्दे पर बनी कि केंद्र और राज्य मिलकर नक्सलवाद से अब पूरी गंभीरता से लड़ेंगे। इसके सफाए के लिए वे नया अभियान चलाएंगे। अन्य बड़े मुद्दों पर चर्चा तो हुई लेकिन मतभेद दूर नहीं हुए। मध्य प्रदेश और गुजरात सहित विपक्षी दलों द्वारा शासित कई राज्यों की तरफ से केंद्र के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए गए। आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई मसलों और प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के कतिपय चर्चित प्रावधानों पर भी सवाल उठे। लेकिन केंद्र के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। ले–देकर यह महत्वाकांक्षी सम्मेलन एक कर्मकांडी आयोजन बन गया। केंद्र–राज्य संबंधों की जटिलता हल करने के लिए वर्ष 1983 में बने बहुचर्चित सरकारिया आयोग की वर्ष 1988 में आई 1600 पृष्ठों की विषद रिपोर्ट और उसकी 247 ठोस सिफारिशों से लैस होने के बावजूद केंद्र सरकार के सामने इस आयोजन में भी ज्यादातर वैसे ही सवाल उठे, जैसा वर्ष 1988 से पहले उठा करते थे। केंद्र से नाराजगी के बावजूद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह आयोजन में शामिल हुए। लेकिन उन तीनों ने केंद्र की भेदभावपूर्ण नीतियों पर सवाल उठाए। मोदी और गृह मंत्री पी. चिदंबरम के बीच तो तनातनी लगातार बनी रही। मोदी ने यह बार–बार जानना चाहा कि उनकी सरकार ने राज्य विधानसभा से जिस ''गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक'' (गुजकोक) को पारित कराकर केंद्र की संस्तुति के लिए भेजा था, उसे केंद्र अपनी मंजूरी क्यों नहीं देना चाहता है। उन्होंने कहा, ठीक इसी तरह का कानून कांग्रेस शासित राज्य महाराष्ट्र में पहले से लागू है। पर गुजरात के मामले में भेदभाव हो रहा है। यह क्या मतलब है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्यों चूकते। उन्होंने भी आंतरिक सुरक्षा की मौजूदा स्थिति की चर्चा करते हुए सवाल उठाया कि केंद्र उनकी सरकार को भी ऐसे ही एक कानून के लिए मंजूरी देने से क्यों कतरा रहा है। आखिर यह कानून संगठित अपराध रोकने के लिए बन रहा है। फिर क्या परेशानी है केंद्र को केंद्रीय गृह मंत्री ने बस इतना कहा कि ऐसे विधेयकों के संदर्भ में संबंधित राज्यों को कुछ सुझाव दिए गए हैं। लेकिन मोदी ने पत्रकारों से साफ–साफ शब्दों में कहा कि केंद्र का यह रवैया गलत है। यह सरकारिया आयोग की भावना के भी प्रतिकूल है।

केन्द्र को कठघरे में खड़ा किया नरेन्द्र मोदी ने

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजकोक का मामला उठाकर एक बार फिर केन्द्र की संप्रग सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि हमें समझ नहीं आता कि गुजकोक के प्रावधानों पर केन्द्र को आपत्ति क्यों हैं। उन्होंने दो–टूक कहा कि आतंकवाद से बिना स्पष्ट रेखा खींचे नहीं निपटा जा सकता। हमें पहले यह तय करना होगा कि कौन लोग उनके हैं और कौन समाज के, तभी इसका निदान निकल सकता है।

दिल्ली में आंतरिक सुरक्षा की बैठक में मोदी केन्द्र को आड़े हाथों लिया उन्होंने आतंकवाद पर केन्द्र के ऊपर राजनीति करने तक का आरोप मढ़ा। गुजकोक पर केन्द्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार उन प्रावधानों का विरोध क्यों कर रही है जो पहले से महाराष्ट्र में हैं। श्री मोदी बोले कि तथाकथित उदारवादी कहे जाने वाले लोकतांत्रिक देश अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया में गुजकोक से भी कड़े प्रावधान वाले कानून हैं बावजूद इसके केन्द्र को गुजकोक के प्रावधान में खामी नजर आ रही है। गुजकोक की वकालत करते हुए मोदी बोले कि इसमें आतंकियों को कड़ी सजा दिए जाने का ही प्रावधान नहीं है बल्कि शिक्षित युवाओं को आतंकी विचारधारा में फंसाने से बचाने का भी उपाय है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक का विरोध वह नहीं समझ पा रहे, विशेष तौर पर तब जब सीमापार से आतंकियों को समर्थन मिल रहा हो। संसद में हमले के आरोपी अफजल गुरू का नाम लिए बगैर मोदी ने

दया याचिका के फार्मूले में बदलाव की बात की। उन्होंने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि राष्ट्र विरोधी, आतंकी और विभाजनकारी गतिविधियों में शामिल लोगों के मामलों को अन्य मामलों से अलग करके देखे।

देश के भीतर पनप रहे वामपंथी उग्रवाद के खतरे की चर्चा करते हुए श्री मोदी बोले कि नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों के कुछ कैडर गुजरात में शरण ले रहे हैं। मोदी ने कहा कि राज्य खुद की सामुद्रिक रिजर्व पुलिस बटालियन बना रहा है जिसके पास अमरीकी एसाल्ट राइफल और स्पिनर राइफल जैसे अत्याधुनिक हथियार होंगे। उन्होंने बताया कि यह बटालियन गुजरात के समुद्र तट के इलाकों की सुरक्षा करेगी और इसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक रैंक का अधिकारी करेगा। मछुआरों को प्रशिक्षण देने का सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि इससे सूचनाएं हासिल करने, पोत यातायात निगरानी प्रणाली को प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

उत्तराखंड ने मांगे ३०० करोड़ रुपए

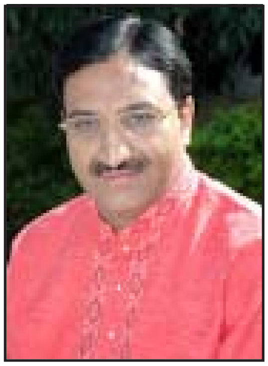

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रदेश में तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और समय–समय पर मेलों में आने वाले लोगों की भारी संख्या को देखते हुए आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार से हर साल 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता की मांग की है।

देश की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की ओर से बुलाई गई बैठक में भाग लेने पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की आबादी मात्र 90 लाख देखकर ही राज्य में पुलिसकर्मियों की जरूरत का आकलन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में समय–समय पर होने वाले मेलों में भीड़ उमड़ती है बड़ी तादाद में तीर्थयात्री और पर्यटक हर साल जुटते हैं। यह सब मिलाकर करीब दस करोड़ की जनसंख्या हो जाती है। इस लिहाज से अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार को हर साल करीब 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता मुहैया करानी चाहिए।

राज्य में पुलिस बल के सशक्तिकरण और मजबूतीकरण के लिए किए गए उपायों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस सुधार संबंधी सूचकों में राज्य ने काफी प्रगति की है। राज्य गठन के बाद पुलिस बल में करीब तेरह हजार भर्तियां की गई हैं। महिलाओं को पुलिस बल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। हर जिले में त्वरित पुलिस बल का गठन किया गया है, भारत–नेपाल सीमा पर 10 विशेष शाखा इकाईयां और छह अतिरिक्त एलआईयू का गठन किया गया है, सभी जिलों को अत्याधुनिक सूचना तकनीक से जोड़ा गया है और हर की पौडी तथा चारधाम यात्रा के लिए अलग से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।

मकोका जैसे म.प्र. के कानून को केंद्र मंजूरी दे : शिवराज सिंह

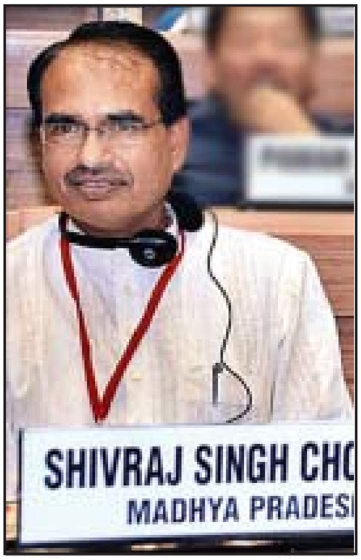

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में भीषण सूखे की स्थिति से निपटने के लिए 11,669.68 करोड़ रुपए की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री से यह मदद अविलंब उपलब्ध कराने की अपील की है। वहीं विज्ञान भवन में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि 2007–08 में सूखे से निपटने के लिए 25,792 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, जिसमें से केंद्र ने चार हजार करोड़ रुपए की सिफारिश की थी, लेकिन आज तक एक रुपया भी नहीं मिला।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और मुद्दा उठाते हुए कहा है कि राष्ट्रपति के पास राज्य सरकार का आतंकवाद पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र के कानून मकोका की तर्ज पर एक अधिनियम लंबित पड़ा है, जिसे केंद्र सरकार को मंजूरी देनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, 1967 के संशोधनों की कई खामियां गिनाते हुए इसे अपर्याप्त बताया।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यह विचार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आंतरिक सुरक्षा पर आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में की। मुख्यमंत्री ने कहा कि टाडा एवं पोटा को लेकर मतभेद रहे हैं और वर्तमान कानून व्यवस्था भी अपर्याप्त है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह ने मांग की कि आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए विशेष बल और अनुसंधान इकाइयों के गठन और प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च की भरपाई केंद्र द्वारा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधनों से आतंकवाद की संपूर्ण व्यवस्था नहीं कर सकती है। चौहान ने कहा कि जिलों में पुलिस बल को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अगले पांच सालों में राज्यों को विशेष अनुदान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण योजना के

लिए 120 करोड़ रुपए के प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे हैं। इसमें से राज्य शासन ने अपने हिस्से की समस्त रकम को तत्काल उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया है। लेकिन अगस्त महीने तक प्रदेश को केवल 50 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना की ही मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि पूर्व गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के कार्यकाल में पुलिस आधुनिकीकरण योजना के लिए राज्य को 112 करोड़ रुपए की रकम प्राप्त हुई थी, जो अब मात्र 50 करोड़ रुपए तक सीमित रह गई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा से संबंधित खर्चे विशेष मद से दिए जाते हैं लेकिन जून 2008 तक बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिलों में योजना लागू करने के बाद इसे हटा दिया गया।

मुख्यमंत्री ने विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 के संशोधनों की खामियां गिनाते हुए कहा कि इस कानून की अन्य धाराओं में आतंकवादियों के लिए चंदा इकट्ठा करने, षड्यंत्र रचने, आतंकवादी कैम्प आयोजित करने और संरक्षण जैसे अपराध के लिए दंड की न्यूनतम अवधि तीन से पांच साल का प्रावधान पर्याप्त नहीं है। श्री चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मांग की कि वह राज्य के अधिकारियों, कर्मचारियों को आतंकवादियों से लड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण देने के लिए एनएसजी एवं अन्य विशेष राष्ट्र स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों में सीटें आवंटित करें। बैठक में राज्य के गृह मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी, पुलिस महानिदेशक एस.के. राउत भी मौजूद थे।

नक्सली हिंसा को राष्ट्रीय आपदा माना जाए : डा.रमन सिंह

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने नक्सली हिंसा को राष्ट्रीय आपादा की श्रेणी में रखने की मांग की है। साथ ही नक्सली हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय आपदा कोष से मदद देने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि मुंबई हमलों को खूब देखा सुना गया, लेकिन नक्सली हिंसा में मारे गए लोगों को लेकर वैसी संवेदना देश के अन्य हिस्सों में नहीं उपजती, इसके उलट नक्सलियों के मामले में महानगरों और विदेशों से आकर कुछ लोग राज्य में प्रदर्शन करते हैं। इस प्रोपेगेंडा से मुकाबले की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है।

मुख्यमंत्री रमन सिंह ने यह बात सोमवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आंतरिक सुरक्षा पर आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कही। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ शुरू किए गए सलवा जुडूम आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने नक्सली समस्या से मुकाबले के लिए सुरक्षा बलों की सीधी कार्रवाई, प्रभावित क्षेत्रों को सामजिक और आर्थिक रूप से मजबूत करना और दिल्ली व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नक्सली प्रोपेगेंडा को रोकने पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि नक्सलवादियों को उनके वर्तमान वर्चस्व को खत्म कर उनका नए क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकना बड़ी चुनौती है, जिसे निपटने के लिए राज्य के वर्तमान संसाधन पर्याप्त नहीं हैं।

उन्होंने नक्सलियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार से एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए मदद मांगी। शहरी मीडिया को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि गांवों की जिंदगी से वाकिफ पत्रकार की रिपोर्टिंग ज्यादा विश्वसनीय होती है, लेकिन कुछ मीडियाकर्मी नक्सलियों की हकीकत को ठीक से न जाने बिना उन्हें महिमा मंडित कर देते हैं।

उन्होंने कहा कि नक्सलवाद अब किसी भी विचारधारा से प्रेरित नहीं है। यह अपराधियों का जमावड़ा, जो कि वन अंचलों पर कब्जा करना चाहते हैंए ताकि वहां से भरपूर वसूली हो सके। उन्होंने कहा कि जब तक नक्सली आतंक पर अंकुश नहीं लगता, तब तक सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य बेकार ही साबित होते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने नक्सलियों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बांग्लादेशियों की घुसपैठ की समस्या गंभीर हैए लेकिन उन्हें उम्मीद है कि विशेष पहचान पत्र जारी करने की केंद्र सरकार की मुहिम से घुसपैठ पर भी रोक लगेगी।

धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़े

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने केंद्र सरकार से धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की है। सूखे को लेकर प्रधानमंत्री से मिले रमन सिंह ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने को लेकर ही अपना जोर रखा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ धान उत्पादक राज्य है और अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ता है तो किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि 36 तहसीलों में 50 फीसदी से कम बारिश हुई है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को एक विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपी है।

मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने नक्सली हिंसा को राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में रखने की मांग की है। साथ ही नक्सली हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय आपदा कोष से मदद देने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि मुंबई हमलों को खूब देखा सुना गया, लेकिन नक्सली हिंसा में मारे गए लोगों को लेकर वैसी संवेदनाा देश के अन्य हिस्सों में नहीं उपजती, इसके उलट नक्सलियों के मामले में महानगरों और विदेशों

से आकर कुछ लोग राज्य में प्रदर्शन करते हैं। इस प्रोपेगेंडा से मुकाबले की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है।

मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने यह बात प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आंतरिक सुरक्षा पर आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कही।

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ शुरू किए गए सलवा जुडूम आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने नक्सली समस्या से मुकाबले के लिए सुरक्षा बलों की सीधी कार्रवाई, प्रभावित क्षेत्रों को सामजिक और आर्थिक रूप से मजबूत करना और दिल्ली व अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर नक्सली प्रोपेगेंडा को रोकने पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि नक्सलवादियों को उनके वर्तमान वर्चस्व को खत्म कर उनका नए क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकना बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने के लिए राज्य के वर्तमान संसाधन पर्याप्त नहीं हैं।

उन्होंने नक्सलियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार से एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए मदद मांगी। शहरी मीडिया को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि गांवों की जिंदगी से वाकिफ पत्रकार की रिपोर्टिंग ज्यादा विश्वसनीय होती है, लेकिन कुछ मीडियाकर्मी नक्सलियों की हकीकत को ठीक से न जाने बिना उन्हें महिमा मंडित कर देते हैं।

उन्होंने कहा कि नक्सलवाद अब किसी भी विचारधारा से प्रेरित नहीं है। यह अपराधियों का जमावड़ा है, जो कि वन अंचलों पर कब्जा करना चाहते हैं, ताकि वहां से भरपूर वसूली हो सके। उन्होंने कहा कि जब तक नक्सली आतंक पर अंकुश नहीं लगता तब तक सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य बेकार ही साबित होते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने नक्सलियों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बांग्लादेशियों की घुसपैठ की समस्या गंभीर है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि विशेष पहचान पत्र जारी करने की केंद्र सरकार की मुहिम से घुसपैठ पर भी रोक लगेगी। ■

आतंकी खतरों पर देर से हरकत में आयी सरकार : राजनाथ सिंह

संप्रग सरकार पर पाकिस्तान से आतंकी खतरों पर देर से हरकत में आने का आरोप मढ़ते हुए भाजपा ने कहा कि सरकार को पड़ोसी देश के साथ तब तक बातचीत नहीं शुरू करनी चाहिए थी, जब तक वह भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल बंद नहीं कर देता।

भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा, 'सरकार घटनाक्रम पर देर से प्रतिक्रिया कर रही है। हमें पाकिस्तान के साथ तब तक बातचीत शुरू नहीं करनी चाहिए जब तक वह अपनी जमीन पर चल रहे आतंकवादी शिविरों को समाप्त करने के जनवरी 2004 के वादे को पूरा नहीं करता।'

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा पाकिस्तान में सक्रिय संगठनों की ओर से भारत पर नए सिरे से आतंकी हमलों की आशंका के बारे में प्रतिक्रिया पूछे जाने पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा लगातार कहती आई है कि जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ लक्षित आतंकवाद के बारे में अपना रूख साफ नहीं करता, उसके साथ बातचीत संभव नहीं है। ■

बिहार में उपचुनाव एक साथ कराए जाएं - राजग

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि बिहार में विधानसभा की खाली सभी 18 सीटों के उपचुनाव एक ही दिन कराए जाएं ताकि इस सूखा प्रभावित राज्य में राहत कार्यों में बाधा नहीं पड़े। आयोग ने 18 में से सिर्फ सात सीटों के उपचुनाव 10 सितम्बर को कराने की घोषणा की है।

भाजपा प्रवक्ता श्री रवि शंकर प्रसाद और जदयू के अध्यक्ष श्री शरद यादव ने इस सिलसिले में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवीन चावला से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा कि बिहार के 38 में से 26 जिले बुरी तरह सूखे की चपेट में हैं। पन्द्रह सितम्बर के बाद स्थिति और भी गम्भीर हो सकती है। इस समय जरूरत बड़े पैमाने पर सूखा राहत अभियान चलाने की है और यदि उपचुनाव कई चरणों में कराए गए तो इसमें बाधा पड़ेगी।

दोनों नेताओं ने कहा कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम सूखा पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर लगभग सभी राजनीतिक दलों के विचार एक जैसे हैं और इसलिए आयोग को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिलने वाले राजग के प्रतिनिधिमंडल में प्रसाद और यादव के अलावा भाजपा के सांसद सैयद शाहनवाज हुसैन भी शामिल थे। आयोग ने बिहार विधानसभा की जिन सात सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है वे हैं—बोचाहा, औराई, कल्याणपुर, वारिसनगर, रामगढ़ चैनपुर और चेनारी। इनके अलावा राज्य विधानसभा की ढोरैया, नौतन, अररिया, घोसी, बोधगया, बेगुसराय, मुंगेर, त्रिवेणीगंज, बगहा, सिमरी बख्तियारपुर और फुलवारीशरीफ सीटें भी खाली हैं। ■

संप्रग सरकार हर मोर्चे पर असफल : भाजपा

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद प्रकाश जावडेकर द्वारा 12 अगस्त, 2009 को जारी प्रेस वक्तव्य

देश के लोग सूखा, स्वाइन फ्लू और महंगाई जैसी तीन आपदाओं को झेल रहे हैं। दुर्भाग्य से इन सभी समस्याओं के प्रति सरकार क्रमिक रूप से अपर्याप्त कार्रवाई करने, अनिर्णय की स्थिति और संवेदनहीनता ही प्रदर्शित कर रही है। सरकार इन प्रमुख समस्याओं से प्रभावी रूप से निपटने में असफल हो चुकी है।

भाजपा, भारत सरकार से चुनौतियों से निपटने और स्थिति का दृढ़ता से सामना करने की अपेक्षा करती है। यदि सरकार वास्तव में कुछ कार्य करना चाहती है तो भाजपा सहयोग और समर्थन देने को तैयार है।

देश के लोग सूखा, स्वाइन फ्लू और महंगाई जैसी तीन आपदाओं को झेल रहे हैं। दुर्भाग्य से इन सभी समस्याओं के प्रति सरकार क्रमिक रूप से अपर्याप्त कार्रवाई करने, अनिर्णय की स्थिति और संवेदनहीनता ही प्रदर्शित कर रही है। सरकार इन प्रमुख समस्याओं से प्रभावी रूप से निपटने में असफल हो चुकी है।

सरकार ने स्वाइन फ्लू संक्रमण को पहले तो नकारा और स्वास्थ्य मंत्री ने डींग मारते हुए कहा था कि भारत को अन्य देशों की तरह स्वाइन फ्लू से घबराने की जरूरत नहीं है।

जब महामारी फैल गई और मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही थी, तब मंत्री जी पूना में प्रथम संक्रमित रोगी कुमारी रिडा शेख को बीमारी फैलाने का कारण बताया। यह संवेदनहीनता की बदतर मिसाल है, इसी घटना पर बाद में उन्हें खेद प्रकट करना पड़ा।

अब महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं कोई निर्णय लेने की बजाय इस बीमारी से निपटने का काम स्थानीय प्रशासन पर छोड़ दिया है और यहां तक कि प्रभावी कदम उठाने के लिए एसएमएस पोल का सहारा ले रही है। ऐसे संकट के समय लोग सरकार से निर्देश देने और निर्णय लेने की आशा रखते है।

सरकार निजी अस्पतालों में समय पर टेस्ट और उपचार करने के लिए आवश्यक पर्याप्त सुविधा देने में असफल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ केन्द्रों पर भीड़, खलबली और अवयवस्था फैल रही है।

जहां तक सूखे का सवाल है, दो वरिष्ठ मंत्री स्थिति को बिलकुल विपरीत बता रहे हैं। विज्ञान और तकनीक मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण जहां सूखे की घोषणा कर रहे है, तो शरद पवार इससे इंकार कर रहे है। यह भ्रम सूखे के संकट से निपटने के सरकार के समय को नष्ट कर रहा है।

सरकार से आशा थी कि सरकार किसानों को सही समय जुलाई में ही प्रभावी मदद प्रदान करती और पर्याप्त निर्देश देती। अब वित्तमंत्री वर्तमान सूखे को ऐतिहासिक सूखा बता रहे है। सरकार को अभी भी जरूरतमंद क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार देने, पानी और चारा देने और जरूरतमंदों को नकद रूप में सहायता देने के लिए आगे आना बाकी है।

महंगाई के मुद्दे पर, सरकार पहले महंगाई बढ़ने से इंकार कर रही थी और इसे अस्थायी बता रही थी। यद्यपि सरकार को दालों और चीनी की कमी का पूर्ण ज्ञान था फिर भी इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने आयात के लिए कुछ भी नहीं किया। यहां तक कि आज भी सरकार के पास चावल की कमी से निपटने की कोई योजना नहीं है।

जब तक की आपूर्ति प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक दाम पर नियंत्रण नहीं होगा और कीमतें लगातार बढ़ती जाएंगी। कल, केवल एक दिन में चीनी की कीमत 400 रू. प्रति क्विंटल बढ़ गई।

लोगों को राहत पहुंचाने और निर्णय नहीं लेने की बजाय प्रधानमंत्री स्वयं और ज्यादा महंगाई बढ़ने की बात कर रहे हैं। यह ऐसी सरकार है जो हर मोर्चे पर असफल रही है। ■

भाजपा की मांगें :

1. *सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत समस्त कार्डधारियों को 30रू प्रति किलों की दर से 5 किलोग्राम दाल तथा 15 रू. प्रतिकिलो की दर से 5 किलो चीनी की आपूर्ति।*
2. *सूखाग्रस्त राज्यों के लिए पर्याप्त धन उपलब्धता।*
3. *आवश्यक क्षेत्रों में पीने के पानी–चारा–रोजगार देने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर योजना बनाए।*
4. *सरकार लोगों को आश्वासन दे कि वह स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए सभी संभव मदद करेगी।*

देश पर मंडराती अकाल की छाया

gjJæ çrki

क्या इस वर्ष देश में अकाल की स्थिति बन रही है?

सरकार तो मुद्रास्फीति दर एक प्रतिशत से कम बता रही है, पर खाने की वस्तुओं के दाम आकाश छू रहे हैं। यानी जमाखोरों को पूरा विश्वास है कि इस साल सूखा पड़ेगा इसलिए अभी से वे लोगों का खून चूसने लगे हैं।

मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इस बार औसत से 5–7 प्रतिशत ही कम वर्षा होगी, लेकिन सरकारी आंकड़े कहीं अलग हैं। देश के करीब ढाई सौ जिले सूखे की चपेट में बताए जा रहे हैं। एक भय का वातावरण व्याप्त है। भारत सरकार और राज्य सरकारें अपने–अपने स्तर पर इस अकाल से निपटने हेतु योजनायें बना रही हैं। जो सरकारी योजनायें बनती हैं उसमें एक महत्वपूर्ण और प्रचलित योजना है किसानों को सस्ती दर पर कर्ज देना। यह कर्ज ज्यादातर नगद न होकर सब्सिडी के रूप में रासायनिक खाद, बीज और कृषि यंत्र पर उपलब्ध कराया जाता है। 60–70 प्रतिशत सब्सिडी और शेष कर्ज के लालच में भोला–भाला साधारण किसान कागज पर अंगूठा लगा देता है। यही 20–30 प्रतिशत कर्ज साल दर साल पहाड़ बनता जाता है। कर्ज न चुकाने की स्थिति में वह आत्महत्या करने हेतु बाध्य होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी कर्ज की वसूली हेतु सरकारी कर्मचारी या पुलिस पहुंचने को गांव के लोग उस व्यक्ति के स्वाभिमान से जोड़कर देखते हैं। इसमें शक नहीं है कि ग्रामीण भारत का किसान स्वाभिमानी होता है।

देश में किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने की खबरें बार–बार आ रही हैं फिर भी सरकारें अपने को किसान हितैषी साबित करने को उतावली हैं। किसानों को कर्ज माफी, कम प्रतिशत पर कर्ज, कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि आदि प्रयास तो बढ़े हैं, पर फिर भी किसानों की आत्महत्यायें रुक क्यों नहीं रही हैं, इसका अध्ययन आवश्यक है।

आत्महत्यायें करने वाले किसान कौन हैं?

यह बात साफ हो चुकी है कि सामान्य या मध्यम वर्ग का किसान ही आत्महत्या करता है। 20 एकड़ से ऊपर जमीन रखने वाला किसान शायद ही आत्महत्या करता हो। देश में जमीन अब कुछ ही लोगों के हाथों में सिमटती चली जा रही है। कर्ज के बोझ तले ग्रामीण भारत का किसान अपनी जमीन बेच कर भूमिहीन होता जा रहा है।

इस देश की जनसंख्या में 2 प्रतिशत लोग अनाज बेचते हैं, 18 प्रतिशत अपने खाने भर लायक अन्न पैदा करते हैं तथा 80 प्रतिशत अनाज बाहर से खरीदते हैं। जो अन्न बेचने वाले हैं वे अपने हाथों से खेती नहीं करते बल्कि ट्रैक्टर से या मजदूरों से खेती करवाते हैं–वे मात्र जमीन के मालिक हैं। अनाज का न्यूनतम मूल्य बढ़ने से मुट्ठी भर लोगों को फायदा होता है, पर 80 प्रतिशत लोगों के समक्ष संकट खड़ा हो जाता है।

देश में थोक भाव में अनाज वही किसान बेचता जो 4 हेक्टेयर जमीन या उससे ऊपर वाली जोत रखता है, शेष किसान तो वर्ष भर खाने भर का भी अनाज पैदा नहीं कर पाते। एक से 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को भी अपने लिए कुछ महीने अनाज खरीदना पड़ता है।

इस देश की जनसंख्या में 2 प्रतिशत लोग अनाज बेचते हैं, 18 प्रतिशत अपने खाने भर लायक अन्न पैदा करते हैं तथा 80 प्रतिशत अनाज बाहर से खरीदते हैं। जो अन्न बेचने वाले हैं वे अपने हाथों से खेती नहीं करते बल्कि ट्रैक्टर से या मजदूरों से खेती करवाते हैं–वे मात्र जमीन के मालिक हैं। अनाज का न्यूनतम मूल्य बढ़ने से मुट्ठी भर लोगों को फायदा होता है, पर 80 प्रतिशत लोगों के समक्ष संकट खड़ा हो जाता है।

आधुनिक खेती के नाम पर कृषि लागत बढ़ती जा रही है। कृषि क्रांति के नाम पर कृषि लागत बढ़ायी गयी, जिसके कारण कृषि कार्य से लोग भागने लगे। यह सही है कि पहले की तुलना में अनाज का उत्पादन बढ़ा है। वर्ष 1950 में देश में लगभग 5 करोड़ टन अनाज का उत्पादन होता था, वह आज लगभग 22 करोड़ टन तक पहुंच गया है। फिर भी अगर कृषि से मुनाफा नहीं हो रहा है तो उसका कारण समझना आवश्यक है।

वर्तमान कृषि में लगने वाला आवश्यक खर्च इस प्रकार है–

१. बीज-

पहले किसान फसल आने पर अच्छी फसल में से कुछ बचाकर रख लेता था और उसे ही अगले वर्ष बीज के रूप में उपयोग में लाता था। अगर किसी किसान का बीज खराब हो जाता था तो दूसरे किसान उसे मुत में बीज दे देते थे। बीज की कीमत लेना निंदनीय माना जाता था।

बाद में, अधिक उत्पादन के लालच में किसानों ने जिस बीज का उपयोग शुरू किया वह बिना रासायनिक खाद के पैदावार नहीं देता तथा फसल में कीड़े लगते हैं अतः फसल की रक्षा हेतु उसे कीटनाशक खरीदने को बाध्य होना पड़ता है। देश में अब अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं जिनसे यह पता चलता है कि 200 वर्ष पूर्व जैविक खेती और फसल चक्र के माध्यम से प्रति हेक्टेयर 20 टन अनाज उत्पादन होता था, पर आज हम आधुनिक

खेती से 7–8 टन प्रति हेक्टेयर ही उत्पादन कर पा रहे हैं।

२.सिंचाई-

देश में 16 करोड़ हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि है जिसमें से लगभग 12 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती है। आजादी के 62 वर्ष पूरे हो गए, यह देश किसान प्रधान है– फिर भी यहां सिंचाई की व्यवस्था अपर्याप्त है।

वर्ष 1999–2000 के कृषि सर्वे के अनुसार पूरे देश में कृषि भूमि का 43.9 प्रतिशत भाग ही सिंचित था, जिसमें कुछ प्रमुख राज्यों की स्थिति इस प्रकार है– पंजाब–96.9 प्रति., हरियाणाः–85.0 प्रति0, उत्तर प्रदेशः–64.9 प्रति0, तमिलनाडुः– 60.7 प्रति0, आन्ध्र प्रदेशः–57.2 प्रति0, बिहारः–49.5 प्रति0, प0 बंगालः–42.3 प्रति0, गुजरात, 37.8, मध्य प्रदेशः– 32.8 प्रति0, राजस्थानः–32.2, उड़ीसाः– 30.4 प्रति0, कर्नाटकः–23.5 प्रति0, महाराष्ट्रः–14.3 प्रति0 तथा असमः–7.6 प्रति0।

प्राचीन भारत में कृषि हेतु सिंचाई की स्वावलंबी व्यवस्था थी। वर्षा का पानी संग्रहित करने के लिए प्रत्येक गांव में तालाब थे। 1793 में अंग्रेजों ने भूमि कानून बनाया, जिसके तहत भूमि निजी एवं सरकारी दायरों में बंट गयी। देश के जंगलों एवं जलाशयों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित होने के कारण जलाशयों की देखभाल की उपेक्षा शुरू हुई। अंग्रेजों ने सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण किया। कृषि हेतु नहरों पर निर्भरता बढ़ने लगी। अंग्रेज जलकर वसूल करने लगे। वर्तमान में सिंचाई हेतु बोरिंग और पम्प लगाये जा रहे हैं। नहरों की उपेक्षा शुरु हो गयी है। तालाब और नहरों से सिंचाई की व्यवस्था में एक फायदा था और वह था भूमिगत जल भण्डार की रक्षा। पर बोरिंग और पम्प तो भूमिगत जल का ही शोषण कर रहे हैं, जिसके कारण भविष्य में पेय जल का संकट भी पैदा होगा। बोरिंग और पम्प हेतु बिजली और डीजल की आवश्यकता पड़ती है। यानी आधुनिक सिंचाई न केवल किसानों पर आर्थिक बोझ डालती है, बल्कि उन्हें परावलंबी भी बनाती है।

अधिक उत्पादन के लालच में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं के उपयोग से न केवल जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है बल्कि भूमि को उर्वरा बनाये रखने वाले मेंढक एवं धामिन सांप भी खत्म हो रहे हैं।

रासायनिक खाद के कारण जैविक खाद की परम्परा खत्म हो गयी। जैविक खाद हेतु पशुपालन आवश्यक था, पर अब न केवल पशुपालन खत्म हो रहा है बल्कि चारागाह भी उजड़ गए हैं। अकाल पड़ने पर सबसे बड़ी समस्या पशुओं के चारे तथा पेय जल की होती है। चारे के अभाव में बूचड़खाने वाले पशुओं को सस्ते दाम पर खरीदते हैं तथा बूढ़े गाय–बैलों की जगह बछड़े बूचड़खाने पहुंच जाते हैं। ग्रामीण भारत आज भी खाना पकाने हेतु कमोबेश गोबर का उपयोग करता है। अगर जानवरों की संख्या इसी तरह घटती रही तो भविष्य का गांव जलावन से वंचित हो जाएगा। गैस पर सब्सिडी का रोना सरकार रोती है। इतने विशाल देश हेतु गैस की आपूर्ति एक समस्या है। भविष्य में खाना बनाने हेतु भी परावलंबन बढ़ने वाला है।

गर्मी के बाद किसान खेत को जोतकर उसमें पानी डालकर धूप में छोड़ देता था। जून–जुलाई की कड़ी धूप में गर्म जल मिट्टी में छुपे कीटाणुओं को मिट्टी से बाहर आने को बाध्य कर देता था। जल पर तैरते इन कीटाणुओं को आकाश में उड़ते पक्षी देख लेते थे तथा खा जाते थे। आधुनिक खेती के नाम पर कीटनाशक का उपयोग स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक हो गया है यह अब किसी से छुपा नहीं है। अगर हम स्वास्थ्य हेतु प्राचीन योग एवं आयुर्वेद को स्वीकार कर सकते हैं तो प्राचीन कृषि व्यवस्था तथा उत्पादन प्रणाली को क्यों नहीं? एक बार इसे भी समय की कसौटी पर कसा जाए। कृषि हेतु नदियों को जोड़कर जल एवं बीज के साथ ही जैविक खाद भी मुत उपलब्ध करायी जाए तो आज का किसान न केवल खेती को लाभकर समझ उसमें रुची लेगा, बल्कि गांवों से पलायन भी रुकेगा।

सब्सिडी या न्यूनतम मूल्य देने के बदले कृषि लागत को कम करें तो किसान के साथ ही अनाज खरीदने वाला 80 प्रतिशत वर्ग भी खुशहाल होगा। पशुओं–पक्षियों के साथ ही भूमिगत जल की रक्षा की भी एक दीर्घकालिक योजना अविलम्ब बने, क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं कि प्रत्येक 12 वर्ष पर मौसम बदल जाता है। 12 वर्ष मौसम साथ देता है तो 12 वर्ष दगा भी देता है। इस बार अकाल की छाया शायद इसी दगा का परिणाम है। ■

सब्सिडी या न्यूनतम मूल्य देने के बदले कृषि लागत को कम करें तो किसान के साथ ही अनाज खरीदने वाला 80 प्रतिशत वर्ग भी खुशहाल होगा। पशुओं–पक्षियों के साथ ही भूमिगत जल की रक्षा की भी एक दीर्घकालिक योजना अविलम्ब बने, क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं कि प्रत्येक 12 वर्ष पर मौसम बदल जाता है। 12 वर्ष मौसम साथ देता है तो 12 वर्ष दगा भी देता है। इस बार अकाल की छाया शायद इसी दगा का परिणाम है।

प्रिय पाठकगण

कमल संदेश (पाक्षिक) का अंक आपको निरन्तर मिल रहा होगा। यदि किन्हीं कारणवश आपको अंक प्राप्त न हो रहा हो तो आप अपने प्रदेश कार्यालय को या हमें अवश्य सूचित करें।

-सम्पादक

सूखे से राहत के लिए कोई दीर्घकालीन योजना नहीं

Vh,l vkj lcze.;e

मध्य अगस्त तक देश में सूखे को आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया गया। कृषि मंत्री ने घोषणा की कि देश के 246 जिले बुरी तरह से सूखे की चपेट में हैं। उड़ीसा से पंजाब तक उत्तर भारत की लगभग 400 किलोमीटर चौड़ी पट्टी खराब मानसून से त्रस्त है। इसमें पश्चिमी यूपीए हरियाणा और पंजाब जैसे भारत के हरित क्षेत्र भी शामिल हैं जो खाद्यान्न उत्पादन के लिए चर्चित हैं। हालात को देखते हुए वित्त मंत्री ने भी कहा कि सूखे का मुकाबला युद्ध स्तर पर किया जाएगा लेकिन उन्होंने यह साफ नहीं किया कि यह युद्ध जीतने के लिए किस तरह की तैयारी की गई है। भारत के लिए सूखा कोई नयी बात नहीं है। हर साल देश के किसी न किसी हिस्से में सूखे की स्थिति रहती ही है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने किसी बड़े सूखे का सामना नहीं किया। जबकि पिछले अनुभव बताते हैं कि सात सालों में एक बार खराब मानसून का आना लगभग तय है।

1966 में पहली बार पूर्वी उत्तर प्रदेश में मेरा सूखा से सीधा सामना हुआ था। यह साल पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार के लिए बेहद खौफनाक था। वास्तव में वह स्वतंत्रता के बाद का पहला साल था जब भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर किसी राज्य के लिए खास राहत कोष घोषित किया था। उसके बाद सूखे या बाढ़ राहत के नाम पर राज्यों के लिए केंद्र से राहत मांगना आम हो गया और राहत कोष की मात्रा केंद्र से उस राज्य के संबंधों पर निर्भर करने लगी। बाद के दिनों में प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत वितरण आम हो गया। इससे विकास कार्य या फिर राहत के लिए आवंटित कोष में लीकेज का मामला भी बढ़ता चला गया। बाढ़ या सूखे की हालत में स्थानीय अधिकारियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय लोगों को सरकारी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का एक तरह से लाइसेंस भी मिल जाता है। ब्रिटिश शासन काल से ही प्राकृतिक आपदा आने पर भूमिहीन मजदूरों और कमजोर किसानों को अल्पावधि रोजगार और वित्तीय सहायता देने की परंपरा रही है। ऐसे समय में कम कीमतों पर खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध कराए जाते रहे हैं। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों में भू–राजस्व भी माफ किया जाता है।

सरकार के कदमों से साफ है कि प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए हमारे पास दीर्घकालीन योजना नहीं है। योजना निर्माण और क्रियान्वयन प्रक्रिया बेहद ढीली है। सिंचाई, वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक, भू–जल संरक्षण, पेड़–पौधों के संरक्षण जैसे मामलों में हम बेहद असफल साबित हुए हैं।

वास्तव में नरेगा भी इसी तरह की राहत योजना है लेकिन अंतर यह है कि यह अच्छे और बुरे दोनों समय में चलाया जाता है। प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए भू–राजस्व काफी पहले खत्म कर दिया गया और दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों प्रकार के कृषि लोन देश भर में माफ किए गए। अच्छे दिनों में भी कृषि लोन माफ करने जैसे प्रोग्राम का क्रियान्वयन एक तरह से यह मान लेना है कि ग्रामीण भारत अक्सर परेशानी में रहता है। केंद्र की हालिया घोषित रणनीति खेत में लगी खरीफ फसल को बचाने और रबी की तैयारी से जुड़ी है। किसी भी फसल सीजन या वार्षिक आयोजन से पहले इस तरह की तैयारी आम है। संभवतः सूखा राहत के नाम पर कुछ हजार करोड़ रुपये और वितरित किए जाएंगे। सरकार ने यह घोषणा भी की है कि खाद्यान्न की कमी की भरपाई के लिए आयात किया जाएगा। लेकिन मुश्किल यह है कि अंतरराष्ट्रीय कृषि उत्पादक समुदाय पहले ही अनाज की कीमतें काफी अधिक बढ़ाने का निर्णय ले चुका है। इससे हमारी समस्या और बढ़ सकती है। इसके अलावा आयात प्रक्रिया सामान्य तौर पर कम से कम एक साल का वक्त लेती है जिससे खाद्यान्न का तुरंत आयात संभव नहीं होगा।

सरकार के कदमों से साफ है कि प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए हमारे पास दीर्घकालीन योजना नहीं है। योजना निर्माण और क्रियान्वयन प्रक्रिया बेहद ढीली है। सिंचाई, वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक, भू–जल संरक्षणए पेड़–पौधों के संरक्षण जैसे मामलों में हम बेहद असफल साबित हुए हैं। सामान्य तौर पर यह समझने की कोशिश नहीं की जाती है कि सूखे से मुकाबले के लिए दीर्घकालीन रणनीति या तैयारी की जरूरत हैए जबकि हर संकट के लिए हम तत्काल रणनीति पर जोर देते हैं। औसत नागरिकों, छोटे किसानों, भूमिहीन श्रमिकों और शहरों की झुग्गियों में रहने वालों के पास कोई सुरक्षा नेट नहीं है। दीर्घकालीन रणनीति के तहत भारत में सेटेलाइट इमैजरी तकनीक में विकास से फसल बीमा व्यवस्था को आकार दिया जा सकता है। इस तरह की रणनीति अपनाकर ही सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है। ■

अल्पसंख्यकों का भाजपा में विश्वास बहाल हुआ है : शिवराज सिंह चौहान

भारतीय जनता पार्टी, अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक 12 एवं 13 अगस्त को भोपाल स्थित पार्टी कार्यालय पं. दीनदयाल परिसर में संपन्न हुई। बैठक का उद्‌घाटन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया व अध्यक्षता मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शाहनवाज हुसैन ने की। जबकि लोकसभा में पार्टी की उपनेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने समापन भाषण दिया। इसके साथ ही सर्वसम्मति से एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हुआ।

eख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक का उद्‌घाटन करते हुए कहा कि अकलियत के बिना संगठन समग्र नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से समूची कौम की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध रही है। उसने कौम को हिन्दू और मुसलमान में नहीं बांटा। मजहब के आधार पर कौम को बांटने का काम कांग्रेस ने किया है। लेकिन वोट बैंक पालिटिक्स से भले ही कांग्रेस को सियासी नफा मिला हो, समाज को और मुल्क को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। अल्पसंख्यक भ्रमित हुए हैं और विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं।

अल्पसंख्यक मोर्चा का आहवान करते हुए उन्होंने कहा कि हमें मिलकर काम करना है और कौम का दिल जीतना है, अकलियत के बीच में जाकर बताना है कि भारतीय जनता पार्टी सबकी हमदर्द है। उनकी भी यहां कर्मठता का मूल्यांकन होता है और अल्पसंख्यकवाद या तुष्टिकरण के आधार पर समाज में फूट पैदा नहीं की जाती है। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस चार दशकों तक अल्पसंख्यकों का भावनात्मक शोषण करती रही है। ऊंचे मंच से कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसमलानों का होगा। सवाल यह है कि यदि कांग्रेस की यह भावना थी तो देश का मुसलमान पिछड़ क्यों गया? उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी में बिना भेदभाव के सबकी हिफाजत की जाएगी। गरीबों में कोई फर्क नहीं किया जाएगा और सबको सामाजिक न्याय और आगे बढ़ने के मौके सुनिश्चित किए जाएंगे। पूर्ववर्ती अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने ऐसा करके दिखा दिया है। मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार ने जो कार्यक्रम आरंभ किए हैं, उनमें मजहब के आधार पर नहीं सबको समान रूप से भलाई के अवसर मिल रहे हैं, फिर चाहे वो मुसलमान हों, हिन्दू अथवा सिख अन्य हों। बैठक की अध्यक्षता मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैय्यद शाहनवाज हुसैन ने की।

पूर्व में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सर्वश्री रामलाल, शिवराज सिंह चौहान, सैय्यद शाहनवाज हुसैन, नरेन्द्र सिंह तोमर, नजाम हेपतुल्ला, माखन सिंह चौहान, विजेन्द्र सिंह सिसोदिया, गौरीशंकर बिसेन, आरिफ बेग सहित अतिथियों ने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पं.दीनदयाल उपाध्याय एवं कुशाभाऊ

ठाकरे के चित्रों पर फूलमालाएं अर्पित की और दीप प्रज्ज्वलित किया। अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कमालभाई लालभाई ने अतिथियों को शाल और श्रीफल भेंट किया। श्री शाहनवाज हुसैन ने मेरा वतन, मेरी जिंदगी (लालकृष्ण आडवाणी की पुस्तक) की प्रति मुख्यमंत्री को भेंट की।

अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हुए हैं : नजमा हेपतुल्ला

भाजपा की वरिष्ठ नेता श्रीमती नजमा हेपतुल्ला ने राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब देश में एनडीए की सरकार चल रही थी, तब वे भाजपा में नहीं थी, लेकिन उन्हें एहसास हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, वही करती है। यहां दोहरे मापदंड नहीं हैं। जबकि कांग्रेस में प्रदर्शन ज्यादा और वास्तविकता कम है। उन्हें इस बात का अहसास तब हुआ, जब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे स्वतंत्रता संग्राम सैनानी आजादी के सिपाही को कांग्रेस ने वह सम्मान नहीं दिया, जो अन्य को दिया गया था। कांग्रेस ने भेदभाव किया। इसने संदेह पैदा किया कि और मुझे अपनी

राजनीति की राह बदलना पड़ी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को निकट से देख चुकी हूं।

उन्होंने कहा कि आडवाणी उदार दिल और खुली किताब की तरह हैं। वे राष्ट्रवाद के कट्टर समर्थक हैं और लौहपुरुष के रूप में उनकी छवि है। लेकिन वे सभी वर्गों, मजहबों के प्रति आदर का भाव रखते हैं और किसी के प्रति कोई दुराव नहीं है। ऐसे में उनकी कट्टरवादी छवि का कभी–कभी गलत अर्थ लगाया जाता है और खौफ पैदा करने की कोशिश की जाती है, जो गलत है।

आडवाणी का मानना है कि मुल्क की तरक्की तभी होगी जब हिन्दू और मुसलमान सभी तरक्की करेंगे। उन्होंने अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशों से आए मेहमानों की दरख्वास्त की कि वे भारतीय जनता पार्टी की उदार छवि जन–जन तक पहुंचेंगे और कांग्रेस द्वारा पैदा किया गया खौफ समाप्त करें। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शानदार विजय मिलेगी। उन्होंने मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यों की भूरि–भूरि प्रशंसा की। और बताया कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चलाई जा रही कन्यादान योजना को उन्हें निकट से देखने का मौका मिला है, यह कार्यक्रम वास्तव में धर्मनिरपेक्षता की जीती–जागती मिसाल है, इसी तरह उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाएं कौम को तरक्की के रास्ते पर ले जा रही हैं, यहां कहीं भी भेदभाव नहीं है। सबको सम्मान, न्याय और तरक्की के अवसर सुलभ किये जा रहे हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यकों के मामले में अब बेनकाब हो गयी है। श्रीमती नजमा हेपतुल्ला ने कहा कि पिछले चुनाव में अल्पसंख्यकों ने मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, बिहार सहित अन्य प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का जोरदारी से समर्थन किया है और आने वाले चुनाव में यह क्रम और तेज होगा। सैय्यद शहनवाज हुसैन के नेतृत्व में अल्पसंख्यक मोर्चा देश में सक्रिय हुआ है। फिर भी हमें हर परिवार तक पहुंचने की आवश्यकता है। जिससे हम कांग्रेस द्वारा फैलाए गए भ्रम को समाप्त कर सकें और भारतीय जनता पार्टी की रीति–नीति, जीवन दर्शन, जीवन मूल्य, जन जन तक पहुंचा सकें। सत्र के बाद प्रदेशों से आए अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्षों ने वृत्त निवेदन प्रस्तुत किया।

अल्पसंख्यक मोर्चा पार्टी के सद्भावना मिशन का संवाहक होगा : सुषमा स्वराज

भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक अथवा मुस्लिम विरोधी नहीं है, हमारा विरोध उस मानसिकता से है, जो समाज को बांटती और नफरत फैलाती है। जो वंदे मातरम् का विरोध करते हैं, आतंकवाद को शह देते हैं और समाज की पीड़ा को नजरअंदाज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और लोकसभा में उप नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने यहां पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक का समापन करते हुए अल्पसंख्यक मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी की सद्भावना मिशन का राजदूत बताया और कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा समाज में सद्भावना का विस्तार करने वाली एक प्रभावी और महत्वपूर्ण संस्था है जो विश्वास दिलाती है और छद्म निरपेक्षतावादी राजनीतिक दलों के दुष्प्रचार को समाप्त करेगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने कांग्रेस और तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के अलंबरदारों के दावों की हवा निकालते हुए कहा कि वास्तव में ये कभी भी अकलियत के हितैषी नहीं रहे। इनका काम नफरत फैलाना और खौफ पैदा करना रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अकलियत का विश्वास जीता है और धीरे–धीरे अकलियत भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हुई है। उन्होंने कहा कि सच्चर कमेटी ने कांग्रेस सहित सभी गैर भाजपा दलों को आईना दिखा दिया है। अल्पसंख्यकों की सर्वाधिक दुर्दशा पश्चिम बंगाल और बिहार में सच्चर कमेटी ने बताई है। इन प्रदेशों में कभी भाजपा का शासन नहीं रहा। हमेशा कांग्रेस, वामपंथियों, राजद आदि दलों का शासन रहा है और उन्होंने अल्पसंख्यकों को पिछड़ेपन के गर्त में धकेल दिया है। सच्चर कमेटी ने इन सभी दलों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये अल्पसंख्यकों के हितैषी नहीं बल्कि उनकी दुर्दशा के लिए जवाबदेह हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने अल्पसंख्यकों से आग्रह किया कि वे ऐसे दलों की बातों पर भरोसा करना छोड़ें और एक बार भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करें। व्यवहार में आए। भाजपा के विचार दर्शन और व्यवहार को परखें। पूर्ववर्ती भाजपानीत एनडीए की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी ने अल्पसंख्यकों को जो सुविधाएं दीं, वे आज तक बेजोड़ हैं। इसी तरह मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार ने अल्पसंख्यकों की तरक्की और हिफाजत के लिए माकूल व्यवस्था की है।

नजदीकियां तकरीरों से नहीं, व्यवहार और आचरण से बढ़ेंगी : कैलाश जोशी

अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी ने कहा कि राष्ट्रवादी मुसलमानों का रुझान आरंभ से ही भारतीय जनसंघ के प्रति रहा है, तब जनसंघ सत्ता से काफी दूर था। लेकिन मुसलमान पार्टी की राष्ट्रवादी नीतियों से आकर्षित हुए थे। वे कांग्रेस की विभाजनकारी नीतियों को समझ चुके थे और उन्हें मालूम था कि कांग्रेस ने नफरत की दीवार खड़ी की है जो किसी दिन तोड़ना ही पड़ेगी। श्री कैलाश जोशी ने कहा कि नफरत की इन दीवारों को तोड़ना है, दूरियां समाप्त करना है। ये भाषण से नहीं काम

करने और दिल जीतने से दूर होंगी।

कांग्रेस अकलियतों की तकलीफों के प्रति मूकदर्शक : प्रभात झा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री प्रभात झा ने अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हिन्दू के लिए गीता सम्मानित ग्रंथ है, उसी प्रकार मुसलमान के लिये कुरान है जिसे वह पढ़ता है। गीता और कुरान ही हिन्दुस्तान है। देश में कमोबेश 18 करोड़ मुसलमान भाई हैं और यही मुल्क के दिल के टुकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी की विरोधी नहीं है। वह सर्वधर्म समभाव की पक्षधर है। श्री प्रभात झा ने कहा कि कांग्रेस भले ही अल्पसंख्यकों की अलंबरदार बनने का दिखावा करे, लेकिन सभी जानते हैं कि जब पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम साहब को कांटीनेटल एयरवेज के सुरक्षा प्रभाग द्वारा अपमानित होना पड़ा कांग्रेस के कान में जूं नहीं रेंगी। उन्होंने (प्रभात झा) ही इस मुद्दे को राज्यसभा के पटल पर उठाया था और ऐयरवेज ने अपनी भूल स्वीकारी थी। कांग्रेस और अन्य गैर भाजपा दलों की धर्मनिरपेक्षता की पोल तो तभी खुल गयी, जब उन्हें हज यात्रियों की बढ़ती तकलीफों पर कोई पीड़ा नहीं हुई।

हज यात्रियों को यहां से रवाना होने से लेकर मक्का पहुंचने तक जो कठिनाइयां सामने आ रही हैं, उनका विरोध मैंने राज्यसभा में किया था और केन्द्र सरकार को सोचने के लिए विवश किया था। कांग्रेस हमेशा अकलियत की तकलीफों के प्रति मूकदर्शक रही है। उसका अकलियत की तकलीफों से लेना देना नहीं रहा। श्री प्रभात झा ने कहा कि अकलियत अब राष्ट्रवादी विचारधारा से आकर्षित होकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे है।

यूपीए सरकार ने घुटने टेके : शाहनवाज हुसैन

भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैय्यद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आजादी के बाद विदेश नीति हमेशा सहमति पर आधारित रही है और कभी विवाद का विषय नहीं बनी, किंतु यूपीए सरकार की घुटना टेक नीति के कारण देश की विदेश नीति को लेकर सभी गैर कांग्रेसी दलों ने विरोध व्यक्त किया है। यह डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार की कूटनीतिक क्षमता पर सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई आसमान पर पहुंच गयी है जिससे आम आदमी की कमर टूट रही है। कांग्रेस ने 205 सीटों पर लोकसभा चुनाव में विजय हासिल की है और वह सत्ता के मद में आम जनता की तकलीफों को भूला चुकी है।

श्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस ने भारतीय समाज में भेदभाव मजहब के आधार पर पैदा कर भिन्नता की जो दीवार बनायी है उसे ढहाने के लिए अकलियत को आगे आना होगा। उन्होंने इस बात का जोरदार खण्डन किया कि भारतीय जनता पार्टी से अल्पसंख्यक दूर है।

उन्होंने कहा कि इस बात का प्रेजेन्टेशन वे दिल्ली में दे चुके हैं कि उन्हें (भाजपा) बूथवार अल्पसंख्यकों के 40 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल हुए हैं। एक अन्य उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि गोपीनाथ मुंडे को भी अल्पसंख्यकों के 80 प्रतिशत वोट हासिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर अल्पसंख्यक आकर्षित हुए हैं और आगे आने वाले चुनाव में अल्पसंख्यकों के शत प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में गिरेंगे। उन्होंने पार्टी के सामूहिक नेतृत्व की सराहना की और बताया कि साम्प्रदायिक दंगे कांग्रेस की बांटने वाली नीतियों की देन रहे है। यह बात अब साबित हो चुकी है कि जहां–जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आयी है वहां मजहबी आधार पर कहीं दंगे नहीं हुए।

अल्पसंख्यक कार्यकर्ता संगठन की अमूल्य निधि : माखन सिंह चौहान

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री श्री माखन सिंह चौहान ने कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा ने कर्मठ कार्यकर्ताओं का चयन किया है। इन कार्यकर्ताओं ने विधानसभा, लोकसभा चुनावों में प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया है। इन्होंने प्रदेश के भीतर और देश के अन्य भागों में अपनी दक्षता प्रमाणित की है। हमें अल्पसंख्यकों के बीच पैठ बनाना है। अल्पसंख्यक पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना है। इनके ऊपर व्यापक जिम्मेवारी होगी। आपने राज्यों से आये अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्षों को पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की सफलता की जानकारी देते हुए कहा कि वे अपने राज्यों में अल्पसंख्यक पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं का विस्तार करें। पढ़े लिखे युवक हमसे जुड़ेंगे और वे बेहतर तरीके से अल्पसंख्यकों के जेहन का भ्रांतियों से मुक्त करने में सफल होंगे।

सियासत नहीं इबादत है - तनवीर अहमद

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तनवीर अहमद ने कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता का वास्तव में सियासत नहीं इबादत है। वह सामाजिक परिवर्तन में जुटा है। वह कौम को जोडकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संवाहक है।

तालीम और तिजारत की ओर बढ़ें : आरिफ बेग

भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री आरिफ बेग ने अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि हम तालीम और तिजारत की ओर बढ़ें और तकरार छोड़ दें। तकरार की नौबत तब सामने आई, जब हम दूसरों के दुष्प्रचार का शिकार हुए और जज्बात में बह गए। अब हमें इससे मुक्त होना हैं। उन्होंने कहा कि –

"लिखी है जो स्याही से वह हम तहरीर बदलेंगे, हम अपने मुल्क के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे, गली, कूचे, दरो दीवार वाशिंदा वही होंगे, मगर चेहरों से मायूसी की यह तस्वीर बदलेंगे" श्री आरिफ बेग ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने दान और माफी में जो संपत्तियां दी थीं, उन पर अतिक्रमण हुए हैं। कांग्रेस की सरपरस्ती में औकाफ की संपत्ति वक्फ की जमीनें गायब हुई।

छत्तीसगढ़ सरकार ने उन अतिक्रमणों को हटाकर अरबों की संपत्ति वक्फ को लौटा दी है। इसी तरह हमें हर राज्य में वक्फ की संपत्ति को अतिक्रमण से मुक्त कराना है। राज्य सरकारों को प्रेरित करने में अल्पसंख्यक मोर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस संपत्ति से हजारों अल्पसंख्यक गरीबों को संबल मिलेगा। ■

खेती पर रेती

– सत्येंद्र रंजन (वरिष्ठ पत्रकार)

भारत को आजादी मिलने के तुरंत बाद जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस देश में बाकी हर चीज इंतजार कर सकती है, लेकिन कृषि नहीं। दो साल पहले किसानों की हालत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंडित नेहरू का हवाला देते हुए यह टिप्पणी आज के संदर्भ में दोहरा दी। मतलब साफ है, देश में बाकी चाहे जो प्रगति हुई होए कृषि की हालत नहीं सुधरी है। किसान आज भी मुसीबत के मारे हैं, इसलिए कि खेती फायदे का धंधा नहीं रही। इस बीच भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा घट कर करीब 17 फीसद रह गया है। आजादी के समय यह हिस्सा तीन चौथाई से भी ऊपर था। यहां तक कि 1980 में कृषि भारत के कुल उत्पाद में 34 फीसदी का योगदान करती थी। अगर अर्थव्यवस्था में किसी क्षेत्र का योगदान घटने के साथ उस क्षेत्र पर निर्भर आबादी में भी उसी अनुपात में कमी आए, तो यह रूझान चिंता की बात नहीं होती।

मगर भारत में ऐसा नहीं है। आज भी तकरीबन 65 फीसदी आबादी खेती या इससे जुड़े धंधों पर निर्भर है। अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र महज 17 फीसदी उत्पादन करता हो और 65 फीसदी लोगों का भार ढोता हो, उसकी हालत कैसी होगीए इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। देश में लगभग 60 फीसदी खेत आज भी सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर हैं। तो जब सूखे की हालत हो, जैसी इस साल बन गई है, तो देश की कितनी बड़ी आबादी के लिए कैसी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैंए इसका भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

देश की ज्यादातर ग्रामीण आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। जो लोग सीधे खेती नहीं करते, उनका कारोबार भी खेती से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में इस बात में कोई हैरत नहीं कि गांवों में कुपोषण आम कहानी है, खासकर महिलाओं और बच्चों में। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक, ये गरीब लोग अपनी आमदनी का करीब दो तिहाई हिस्सा भोजन पर खर्च कर देते हैं। यानी कपड़ा, मकान, इलाज और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए उनके पास संसाधन ही नहीं बचते। अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी ने तीन साल पहले अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश के 77 फीसदी लोग रोज 20 रूपए से कम पर गुजारा करते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग ग्रामीण हैं। गांव जब ऐसे गरीब लोगों का बसेरा हैं, तो जाहिर है उनकी दशा भी वैसी ही है। गांधीजी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन आज ज्यादातर गांवों में सिर्फ बदहाली, बीमारियों और अशिक्षा का बसेरा है। इसीलिए आजादी के छह दशक बाद भी गांवों से लोगों का शहरों की तरफ पलायन जारी है। आज बहुत से ऐसे गांव हैं, जहां जवान मर्द देखने को नहीं मिलते। उन्हें शहरों में मजदूरी और वहां की झुग्गी बस्तियां में रिहाइश गांवों से बेहतर मालूम पड़ती है। आखिर इस हाल के लिए कौन जिम्मेदार है। अब यह सरकारी स्तर पर भी माना जाने लगा है कि जिम्मेदार आखिरकार आजादी के बाद से अपनाई गई सरकारी नीतियां ही हैं।

विकास नीति में उघोगों को अहमियत देना शायद वक्त की जरूरत थीए लेकिन इन उद्योगों का समान रूप से क्षेत्रीय विस्तार हो या कृषि आधारित उद्योगों का देश भर में जाल बिछाया जाए– इस जरूरत की अनदेखी क्यों की गई फिर अर्थव्यवस्था में अगर उद्योग और सेवा जैसे क्षेत्रों का योगदान बढ़ता गयाए तो उसी अनुपात में ग्रामीण आबादी खेती से हटकर इनसे क्यों नहीं जुड़ सकी। नीतियों के इसी असंतुलन ने आज गांव और शहर के बीच बेहद चौड़ी खाई बना दी है। उद्योग और सेवा क्षेत्रों से जुड़े लोगों की आमदनी और खेती एवं उससे संबंधित पेशों से जुड़े लोगों की आमदनी का फासला हर दशक के साथ बढ़ता गया है। बात बुनियादी ढांचे की हो या मानव विकास के लिए जरूरी ढांचे की– गांवों को आबादी के अनुपात में उनका हिस्सा नहीं मिला है। बहरहाल, अब जबकि यह फर्क और विकास की कसौटियों पर गांवों की दुर्दशा को सरकारी तौर पर भी स्वीकार किया जाने लगा है, तब भी यह सवाल कायम है कि क्या इससे सूरत बदलेगी। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून और आदिवासी एवं अन्य वनवासी भू–अधिकार कानूनों से एक हलकी सी पहल जरूर हुई है। अगर सरकार खाद्य अधिकार कानून भी बना कर उस पर अमल करेए तो इस प्रयास को कुछ और बल जरूर मिलेगा। इन कानूनों से ग्रामीणों की आमदनी बढ़ने, देहाती इलाकों में सार्वजनिक संपत्तियों का विकास होने और सबसे बड़ी बात कि लोगों को भोजन मिलने की संभावना पहले से बेहतर होगी। इससे पलायन भी घट सकता है, लेकिन गांवों की सूरत असल में तब तक नहीं बदलेगी, जब तक खेती मुनाफे का धंधा नहीं बनती। यह तब तक नहीं हो सकता, जब तक सिंचाई, बीज और कृषि मार्केटिंग की व्यवस्था सरकारी नीतियों के केंद्र में नहीं आती। अगर यह मुमकिन हो सके और गांवों में वहां के संसाधनों से चल सकने वाले उद्योगों का जाल बिछाया जा सके, तो गांव सचमुच रहने की जगह बन सकते हैं।

ज्यादातर मतदाताओं के गांवों में रहने के बावजूद ये बातें राजनीति का मुद्दा नहीं हैं। जब तक इन मुद्दों से राजनेताओं की तकदीर तय नहीं होगी, सरकार की नीतियां घिसे–पिटे ढर्रे पर चलती रहेंगी। जब समस्या बहुत बुनियादी होए बात खाने से आगे नहीं बढ़ पा रही हो, तो ग्रामीण विकास के दूसरे पहलुओं पर चर्चा अप्रासंगिक है। बीते 62 साल खेती और गांवों के नहीं, बल्कि असंतुलित विकास के रहे हैं। ये शहर और गांव, गरीब और अमीर की खाई बढ़ाने वाले साल रहे हैं। और आजादी के 63वें साल में भी हालात में बुनियादी बदलाव के कोई संकेत नहीं हैं। ■

भाजपा ने की राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग

मणिपुर राज्य उबल रहा है। पुलिस कमांडों द्वारा सैंकड़ों लोगों की उपस्थिति में भरे बाजार में दिन–दहाड़े संजीत सिंह और रबीना देवी को फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने की घटना ने राज्य के लोगों की आत्मा को झकझोर डाला है। गत 15 दिनों से लगातार विरोध–प्रदर्शनों ने राज्य को पंगु बना दिया है। वहां की स्थिति अतिशय गंभीर हो उठी है, जिस पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी के एक शिष्टमंडल ने जिसमें संसद सदस्य श्री प्रकाश जावडेकर, श्रीमती विजया चक्रवर्ती, श्री राजन गुहेन और श्री रमन डेका शामिल थे, 18 अगस्त को इम्फाल का दौरा किया था और उसने सभी विरोधी दलों, गैर–सरकारी संगठनों, सिविल कार्यकर्ताओं, एसएचआरसी के साथ बातचीत की थी। यह शिष्टमंडल पीड़ितों के परिवारों से भी मिलने गया था। शिष्टमंडल ने राज्यपाल से भी मुलाकात की थी।

पुलिस ने संजीत सिंह और रबीना देवी को राज्य विधानमंडल से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर मार डाला था। उस समय राज्य विधानमंडल का सत्र चल रहा था। मुख्यमंत्री ने सदन को सूचित किया था कि पुलिस ने उस मिलिटेंट को मार डाला है, जो मार–काट मचा रहा था। किंतु, फोटो के देखने पर और गवाहों तथा जो घायल हुए थे, उनके राज्य मानव अधिकार आयोग के सामने दिए गए बयान से सरकार और मुख्यमंत्री के झूठ का पर्दाफाश हो गया था।

गत सात महीनों के दौरान पुलिस द्वारा 219 से भी अधिक लोग मारे गए, जिनमें से कई निर्दोष थे और झूठी मुठभेड़ में मार डाले गए थे। हाल ही में इंडियन रिजर्व बटालियन के सदस्यों द्वारा यूनीवर्सिटी के डीन श्री इस्लामुद्दीन को मार डाला गया था।

लोगों में मुख्यमंत्री श्री इबिबो सिंह के विरूद्ध भारी आक्रोश है, जो राज्य विधानमंडल को गुमराह करने के दोषी हैं, जो कुछ आतंकी गिरोहों को संरक्षण देने के दोषी हैं, जो पुलिस और प्रशासन को भ्रष्ट बनाने के दोषी हैं, जो राज्य मानव अधिकार आयोग में कर्मचारियों की कमी को पूरा न करने के दोषी हैं।

राज्य में सांविधानिक मशीनरी पूरी तरह चरमरा गई है क्योंकि राज्य में बिजली की बेहद कमी है, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, चिकित्सा सुविधाएं सुलभ नहीं है, बेरोजगारी का आलम है, आवश्यक वस्तुओं के लिए कोई सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं है और चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है।

भाजपा मांग करती है :

- राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।
- मुख्यमंत्री श्री इबिबो सिंह को बर्खास्त किया जाए।
- 23 जुलाई की फर्जी मुठभेड़ में लिप्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामले दर्ज किए जाएं और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ■

पुस्तक में व्यक्त विचार भाजपा का दृष्टिकोण नहीं : राजनाथ सिंह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी श्री जसवंत सिंह द्वारा लिखित पुस्तक "जिन्ना भारत विभाजन के आईने" में उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से अपने को पूर्णतः अलग करती है। पुस्तक में व्यक्त विचार किसी भी रूप में भाजपा के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

भारत विभाजन में जिसके द्वारा इतिहास के उस कालखंड में उत्पन्न अस्थिरता और करोड़ों लोगों के बेघरबार होने के दुःखद घटनाक्रम में मुहम्मद अली जिन्ना की भूमिका जगजाहिर है। इतिहास की इस दुःखद त्रासदी को हम भुला नहीं सकते।

सरदार वल्लभभाई पटेल ने विभाजन के उस चुनौती भरे नाजुक दौर में देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने में एक एतिहासिक भूमिका निभाई। संपूर्ण राष्ट्र सरदार पटेल के प्रति कृतज्ञ है और उनकी दूरदृष्टि, साहस और नेतृत्व क्षमता पर गर्व का अनुभव करता है। ■

नरेन्द्र मोदी को एफडीआई एशियन विनर अवार्ड

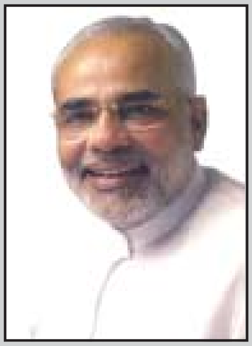

वाणिज्य क्षेत्र की विश्वविख्यात एफडीआई पत्रिका ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को पर्सनालिटी, एशियन विनर 2009 अवार्ड देने की घोषणा की है। पिछले साल राज्य में 2.8 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आकर्षित करने और गुजरात को वैश्विक निवेश के पसंदीदा स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए नरेन्द्र मोदी को इस अवार्ड के लिए चुनाव गया है। पत्रिका के मुताबिक लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने मोदी ने नेतृत्व में गुजरात ने पिछले साल भारत के कुल विदेशी निवेश का 10.3 फीसदी हिस्सा आकर्षित किया था। इससे राज्य का तीव्र विकास हुआ है।■